▸▸ वर्ष : 35 ▸▸ अंक : 19 ▸▸ मुंबई, गुरुवार, 2 अप्रैल 2026 ▸▸ RNI: MAHHIN/49994/91 ▸▸ मूल्य : 3 रुपए ▸▸ epaper.dobajedopahar.com ▸▸ संपादक : अरुण लाल ▸▸ संरक्षक : एन. के. पुरोहित

DBD दो बजे दोपहर

पत्रकारिता पावर नहीं रिस्पांसिबिलिटी है

राहत के फैसले

साकलाई सिंचाई योजना को 1234 करोड़ की मंजूरी

सरकार ने अहम कदम उठाते हुए साकलाई लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए 1,234 करोड़ रुपये से ज्यादा की मंजूरी दी है। यह योजना अहिल्यानगर जिले के श्रीगोंदा तालुका के चिखली क्षेत्र में लागू की जाएगी। इस योजना के तहत घोड़ बांध के जलाशय से पानी 4 चरणों में उठाकर 32 गांवों तक पहुंचाया जाएगा। इससे सूखा प्रभावित इलाकों को बड़ी राहत मिलेगी। करीब 9,600 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई सुविधा मिलेगी और गांवों में पेयजल की समस्या भी काफी हद तक दूर होगी। योजना में तालाब, सीमेंट नाला बांध और अन्य जलसंचयन संरचनाओं का निर्माण भी शामिल है, जिससे पानी का बेहतर उपयोग हो सकेगा।

'सर्वेयर' पद का नाम बदला, कर्मचारियों को राहत

राजस्व विभाग ने भूमि अभिलेख विभाग में 'सर्वेयर' पद का नाम बदलकर 'परिरक्षण सर्वेयर' करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही इस पद पर अब पदोन्नति और विभागीय भर्ती दोनों के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी, जिससे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। राजस्व विभाग ने अमरावती जिले में भव्य खेल परिसर के निर्माण के लिए 16,708 वर्ग किलोमीटर भूमि आवंटित करने को मंजूरी दी है। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं और आधुनिक बुनियादी ढांचा मिल सकेगा।

धीरज सिंह । मुंबई

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की. इन फैसलों में सिंचाई परियोजना, नदी पुनर्जीवन, खेल सुविधाएं, आरक्षण व्यवस्था और दिव्यांग छात्रों की मदद जैसे कई मुद्दे शामिल रहे। साथ ही एलपीजी को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार को युद्धस्तर पर पूरा करने का आदेश दिया है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में जल्द से जल्द पाइप नेचुरल गैस का नेटवर्क मजबूत किया जाए ताकि एलपीजी पर निर्भरता कम हो सके।

▸▸ महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण फैसलों को दी मंजूरी

कैबिनेट के फैसले के अनुसार गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए लंबित सभी अनुमतियों को अब 'मंजूर' माना जाएगा और नए आवेदनों को 24 घंटे के भीतर मंजूरी दी जाएगी। काम में तेजी लाने के लिए सड़क मरम्मत शुल्क माफ कर दिया गया है और कंपनियों को 24 घंटे काम करने की अनुमति दी गई है।

▸▸ पीएनजी अब अत्यावश्यक सेवा, गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए एनओसी की जरूरत नहीं

इसके अलावा, अब अग्निशमन विभाग या ट्रैफिक पुलिस से एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सभी नियमों और शर्तों को शिथिल कर दिया गया है। सरकार ने पीएनजी को अब पानी और बिजली की तरह 'अत्यावश्यक सेवा' श्रेणी में शामिल कर दिया है। घरेलू उपयोग को प्राथमिकता देते हुए होटल, स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक रसोई और हॉस्टलों को कमर्शियल दरों पर 50 प्रतिशत आपूर्ति की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए राशनिंग नियंत्रक और नागरिक आपूर्ति निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा।

▸▸ सिंचाई के लिए 1234 करोड़ मंजूर, छात्रों को भी मिली बड़ी राहत

दिव्यांग छात्रों की छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी

दिव्यांग कल्याण विभाग ने 8वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाने का निर्णय लिया है। करीब 12 साल के लंबे इंतजार के बाद लिया गया यह फैसला हजारों छात्रों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।

नदियों को बचाने के लिए नया प्राधिकरण

राज्य में बढ़ते नदी प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने महाराष्ट्र राज्य नदी पुनर्जीवन प्राधिकरण बनाने का फैसला किया है। यह प्राधिकरण राज्य की 54 प्रदूषित नदी पट्टियों को साफ करने और पुनर्जीवित करने का काम करेगा। इसमें नर्मदा, तापी, गोदावरी और कृष्णा जैसी बड़ी नदियां भी शामिल हैं। प्राधिकरण सांडपानी प्रबंधन, औद्योगिक कचरे पर नियंत्रण, अतिक्रमण हटाने और जनजागरण जैसे काम करेगा। इस योजना के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि राज्य सरकार 100 करोड़ रुपये का योगदान देगी. बाकी राशि अन्य स्रोतों से जुटाई जाएगी।

आरक्षण उप-वर्गीकरण पर उच्च स्तरीय समिति गठित

सामाजिक न्याय विभाग ने अनुसूचित जाति आरक्षण के उप-वर्गीकरण के मुद्दे पर अध्ययन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। यह समिति प्राप्त विभिन्न मांगों और आवेदनों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देगी।

आम और काजू किसानों को अधिक मदद का आश्वासन

कैबिनेट बैठक में आम और काजू किसानों को मिलने वाली सरकारी सहायता पर भी चर्चा हुई। मंत्री नितेश राणे ने बताया कि किसानों को वर्तमान में मात्र 220 रुपये की सहायता मिलती है, जो बेहद कम है। इस पर उदय सामंत और अन्य मंत्रियों ने किसानों के समर्थन की मांग की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए आम और काजू किसानों को अधिकतम सहायता देने के निर्देश दिए। साथ ही, संबंधित विभागों को प्रस्ताव तैयार कर जल्द निर्णय लेने को कहा गया।

सुनेत्रा पवार चलीं दिल्ली

अमित बृज । मुंबई

बारामती प्लेन क्रैश में अजित पवार को खोने के बाद कठिन दौर से गुजर रही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रूपाली चाकणकर के अशोक खरात केस में फंसने और फिर मंत्री नरहरि जिरवाल का किन्नर के साथ वीडियो वायरल होने के कारण कई चुनौतियों का सामना कर रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी सुनेत्रा पवार को बारामती से उपचुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचना है। इसके लिए हलचल अब तेज हो गई है। एनसीपी (अजित पवार गुट) की अध्यक्ष सुनेत्रा पवार दिल्ली पहुंची हैं। यहां उनके कई अहम राजनीतिक नेताओं से मिलने का कार्यक्रम तय माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, इस दौरे को बारामती उपचुनाव की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

बारामती : भावनात्मक अपील और निर्विरोध की मांग

अजित पवार गुट की ओर से सुनेत्रा पवार को मैदान में उतारा गया है। यह सीट एक दिवंगत नेता (पूर्व उपमुख्यमंत्री) से जुड़ी होने के कारण काफी संवेदनशील है। राकां (अजित पवार गुट) महाराष्ट्र की पुरानी परंपरा का हवाला देते हुए मांग कर रहा है कि चुनाव निर्विरोध (बिना किसी विरोध के) कराया जाए। चौंकाने वाली बात यह है कि शरद पवार गुट ने भी संकेत दिए हैं कि वे बारामती में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे।

सुनेत्रा पवार कर सकती हैं पीएम मोदी और खरगे से मुलाकात

सुनेत्रा पवार का दिल्ली मिशन

नामांकन से पहले सुनेत्रा पवार दिल्ली रवाना हुई। वे वहां पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलकर चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगी। साथ ही, बारामती चुनाव को निर्विरोध कराने के लिए वे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात कर सकती हैं, ताकि एक सर्वसम्मति बनाई जा सके।

राहुरी : भाजपा का कार्डिले पर दांव

राहुरी सीट पर भाजपा ने दिवंगत नेता शिवाजीराव कार्डिले के बेटे अक्षय कार्डिले को उम्मीदवार बनाकर 'युवा और विरासत' का कार्ड खेला है। वहीं, शरद पवार गुट यहाँ चुप बैठने के मूड में नहीं है; सूत्रों की मानें तो प्राजक्ता तनपुरे को यहाँ से मैदान में उतारा जा सकता है, जिससे मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है।

कांग्रेस की एंट्री और सियासी पेंच

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मामले में नया ट्विस्ट ला दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अगर शरद पवार गुट इन सीटों पर नहीं लड़ता है, तो कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार है। कांग्रेस की इस सक्रियता ने महाविकास अघाड़ी (MVA) के भीतर के समीकरणों को गरमा दिया है।

बांद्रा-कुर्ला स्टेशनों से बीकेसी का सफर होगा आसान

'पॉड टैक्सी' का आज होगा भूमिपूजन

दीपक पवार । मुंबई

मुंबई के सबसे व्यस्त बिजनेस हब बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अब ट्रैफिक जाम की चिक-चिक गुजरे जमाने की बात होने वाली है। एमएमआरडीए ने बांद्रा और कुर्ला स्टेशनों से बीकेसी के बीच 8.8 किमी लंबी 'पॉड टैक्सी' चलाने का बीड़ा उठाया है। शुक्रवार, 3 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री के हाथों इस हाई-टेक प्रोजेक्ट का भूमिपूजन होने जा रहा है। बीकेसी दुनिया भर के बड़े ऑफिसों का ठिकाना है, लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए बांद्रा या कुर्ला स्टेशन से घंटों जाम में फंसना पड़ता है। इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत यह पॉड टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है।

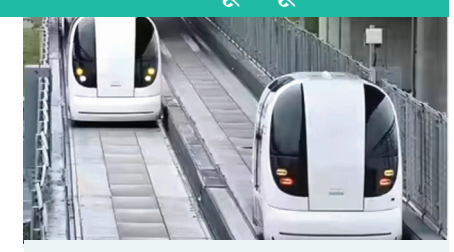

लंदन के हीथ्रो वाली विदेशी तकनीक

इस प्रोजेक्ट का जिम्मा हैदराबाद की 'साईं ग्रीन मोबिलिटी' को मिला है, जिसने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर पॉड टैक्सी चलाने वाली कंपनी 'अल्ट्रा पीआरटी' के साथ हाथ मिलाया है। यानी मुंबईकरों को अब इंटरनेशनल लेवल की सुरक्षा और सुविधा अपने शहर में मिलेगी। भूमि अधिग्रहण और कागजी कार्रवाई की वजह से इस प्रोजेक्ट में थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन अब रास्ता साफ है। शुक्रवार के भूमिपूजन के बाद निर्माण कार्य तेज कर दिया जाएगा।

ब्रीफ न्यूज़

महाराष्ट्र में 14,726 वन अधिकार दावे लंबित

मुंबई। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर के दौरान जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके ने जानकारी दी कि महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र में आदिवासी समुदाय वन अधिकार कानून, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन और भूमि विवादों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आदिवासियों का आरोप है कि उनके भूमि संबंधी दावों को उचित तरीके से स्वीकार नहीं किया जा रहा है, जिसकी पुष्टि सरकारी आंकड़े भी करते हैं। आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2026 तक महाराष्ट्र में व्यक्तिगत वन अधिकारों के कुल 14,726 मामले लंबित हैं, जिनमें 6,158 दावे और 8,568 अपीलें शामिल हैं।

आईएसआईएस आतंकी को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति सुमन श्यामन की पीठ ने कथित आईएसआईएस आतंकी शामिल साकिब नाचन की उस याचिका को निपटा दिया है, जिसमें उसने भायखला जेल में जान का खतरा बताते हुए ट्रांसफर की मांग की थी। नाचन के वकील ने दलील दी कि भायखला जेल के सीसीटीवी कैमरे बंद रहते हैं और उस पर तलोजा जेल जैसी हिंसक घटना दोबारा हो सकती है, जहाँ पिछले साल साथी कैदियों ने उस पर हमला किया था। हालांकि, हाई कोर्ट ने उसे इस राहत के लिए निचली अदालत में गुहार लगाने का निर्देश दिया है।

'स्मार्ट' हुई लालपरी

सीएम फडणवीस ने लॉन्च किया 'रुपे ऑन द गो' कार्ड

देवेंद्रनाथ जैसवार । मुंबई

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को 'रुपे ऑन द गो' एनसीएमसी (नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) सक्षम स्मार्ट कार्ड योजना का लोकार्पण किया। मुंबई स्थित मंत्रालय में आयोजित इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार और परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक भी मौजूद रहे।महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (एमएसआरटीसी) ने विभिन्न सामाजिक वर्गों के लिए यात्रा को अधिक सुलभ, पारदर्शी और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से इस कार्ड को लॉन्च किया है। राज्य सरकार ने रियायती यात्रा का लाभ लेने वाले सभी यात्रियों के लिए इस कार्ड को अनिवार्य कर दिया है।

'वन नेशन, वन कार्ड' की दिशा में कदम

एनसीएमसी कार्ड 'एक राष्ट्र, एक कार्ड' की अवधारणा पर आधारित है। यह कार्ड केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देशभर में मेट्रो और अन्य राज्यों की बस सेवाओं में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।

किन्हें मिलेगा स्मार्ट कार्ड का लाभ?

इस योजना के तहत विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं और अन्य सवलतधारक यात्रियों को आधार से लिंक किए गए एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड वितरित किए जाएंगे। इससे यात्रियों को बस यात्रा में मिलने वाली छूट का लाभ आसानी से मिलेगा।

'लालपरी' बसों में अब अनिवार्य हुआ कार्ड

एमएसआरटीसी की 'लालपरी' बसों में विभिन्न श्रेणियों के तहत मिलने वाली रियायतें अब केवल इसी कार्ड के माध्यम से उपलब्ध होंगी। इससे टिकटिंग प्रणाली अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनेगी। राज्य में वरिष्ठ नागरिकों को पहले से ही किराए में छूट मिलती है। 65 से 75 वर्ष के लोगों को 50 प्रतिशत और 75 वर्ष से अधिक आयु वालों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है। महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 50 प्रतिशत छूट मिलती है, जबकि छात्रों और दिव्यांगों को भी विशेष रियायतें मिलती हैं।

खरात को 14 दिन की जेल

100 से ज्यादा शिकायतें, 10 FIR

डीबीडी संवाददाता । नासिक

पुणे और नासिक में खुद को 'गॉडमैन' बताकर महिलाओं का शोषण करने वाले ढोंगी बाबा अशोक खरात की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार को नासिक कोर्ट ने पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत (जेल) में भेज दिया है। बुधवार को महाराष्ट्र पुलिस की एसआईटी ने अशोक खरात को सेशन जज बी एन इछपुरानी के सामने पेश किया। पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद कोर्ट ने खरात को 14 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अब उसे नासिक रोड सेंट्रल जेल में रखा जाएगा।

परिवार पर भी कसता शिकंजा

जांच एजेंसियां अब खरात के परिवार की भूमिका की भी जांच कर रही हैं। बुधवार रात एसआईटी ने खरात के बेटे हर्षवर्धन को उसके करमयोगी नगर स्थित घर से हिरासत में लेकर पूछताछ की, हालांकि बाद में उसे रिहा कर दिया गया। वहीं, आरोपी बाबा की पत्नी फिलहाल फरार बताई जा रही है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है।

शिकायतों का अंबार 800 से ज्यादा पीड़ित

बाबा का जाल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 800 से ज्यादा शिकायतें सामने आ चुकी हैं। 10 एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें से 8 यौन उत्पीड़न और 2 धोखाधड़ी से जुड़ी हैं। एसआईटी को हेल्पलाइन नंबर के जरिए भी 100 से ज्यादा कॉल मिले हैं।

यौन शोषण के वीडियो अश्लील साइटों पर

मामले का सबसे डरावना पहलू यह है कि खरात द्वारा बनाए गए पीड़ितों के अश्लील वीडियो कथित तौर पर अश्लील साइटों तक पहुँच गए हैं। इस वजह से कई पीड़ित महिलाएं गहरे सदमे में हैं और बदनामी के डर से बाहर निकलने के बजाय घर से काम करने को मजबूर हो गई हैं।

मैं निर्दोष हूं : मंत्री झिरवल

▸▸ वीडियो कांड पर मंत्री ने पार्टी प्रमुख सुनेत्रा को फोन कर दी सफाई

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

महाराष्ट्र की राजनीति में मंत्री नरहरी झिरवल के एक विवादित वीडियो ने भूचाल ला दिया है। बुधवार तक इस मामले ने न केवल कानूनी मोड़ ले लिया है, बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजीत पवार गुट) के भीतर की अंदरूनी कलह को भी चौराहे पर ला खड़ा किया है। विवादों में घिरने के बाद नरहरी झिरवल ने सुनेत्रा पवार को फोन कर अपना पक्ष रखा और स्पष्ट किया कि वे इस पूरे प्रकरण में पूरी तरह निर्दोष हैं। उन्होंने नासिक जिला पुलिस प्रमुख को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की है।

धनंजय मुंडे पर सीधा हमला

इस आग में घी डालने का काम करुणा मुंडे के बयानों ने किया है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि यह वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि खुद धनंजय मुंडे ने वायरल करवाया है। करुणा का दावा है कि धनंजय को बड़े मंत्री पद की जल्दी है, इसलिए उन्होंने झिरवल को फंसाने की यह साजिश रची है। करुणा मुंडे ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस पूरे मामले की एसआईटी (SIT) जांच होनी चाहिए।

संसद सत्र ▸ विपक्ष के संशोधनों को खारिज करते हुए सदन ने ध्वनिमत से किया पारित

जन विश्वास विधेयक को लोकसभा की मंजूरी

एजेंसी । नई दिल्ली

लोकसभा ने बुधवार को 'जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026' को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले सदन ने विपक्ष द्वारा पेश किए गए सभी संशोधनों को खारिज कर दिया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री Piyush Goyal ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य भय नहीं, बल्कि कर्तव्य पर आधारित विश्वास की संस्कृति विकसित करना है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक लोगों को सुधार का अवसर देने की सोच के साथ लाया गया है।

छोटी गलतियों पर मिलेगी चेतावनी

सरकार के अनुसार, प्रस्तावित कानून में चरणबद्ध कार्रवाई का प्रावधान है। पहली बार छोटी गलती होने पर चेतावनी दी जाएगी, दूसरी बार दंड लगाया जाएगा और तीसरी बार गंभीरता के आधार पर कड़ी सजा तथा अदालती कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है।

एक हजार से अधिक प्रावधान होंगे सरल

इस विधेयक के जरिए करीब 1,000 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाकर उनका सरलीकरण किया जाएगा। इससे आम नागरिकों और छोटे उद्यमों को राहत मिलेगी और छोटी-मोटी गलतियों के लिए अदालत के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मंत्री ने कहा कि सरकार दंड आधारित पुरानी व्यवस्था को बदलकर न्याय आधारित प्रणाली विकसित करना चाहती है।

समिति की सिफारिशों के बाद लाया गया विधेयक

गौरतलब है कि यह विधेयक पहले 2025 में लोकसभा में पेश किया गया था और बाद में इसे प्रवर समिति को भेजा गया था। समिति की सिफारिशों को शामिल करने के बाद संशोधित रूप में इसे पारित किया गया। चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने विधेयक की आलोचना की। कुछ सदस्यों ने इसे आम जनता के साथ विश्वासघात बताते हुए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मांग की।

टेनिस क्रिकेट का महाकुंभ

▸▸प्रेसिडेंट कप इंडिया 2026 का भव्य आगाज
▸▸दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में भव्य उद्घाटन

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

ठाणे के दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में टेनिस क्रिकेट का रोमांच चरम पर है। टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया (आईटीसीएसएफ) के अध्यक्ष सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे की पहल पर पहली बार 'प्रेसिडेंट कप इंडिया 2026' टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता का शुभारंभ मंगलवार शाम रंगारंग समारोह के साथ हुआ। उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की विशेष उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भव्य बना दिया। इस मौके पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मेयर शर्मिला पिम्पोलकर और आयुक्त सौरभ राव सहित कई गणमान्य मौजूद रहे।

क्रिकेटमय माहौल, हजारों दर्शकों की उमड़ी भीड़

लंबे समय बाद दादोजी स्टेडियम में क्रिकेट का जोश देखने को मिल रहा है। हजारों दर्शकों की मौजूदगी में देशभर के विभिन्न राज्यों से आई टीमें मैदान में अपना दमखम दिखा रही हैं। यह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता दर्शकों के लिए मुफ्त रखी गई है, जिससे खेल प्रेमियों में खास उत्साह देखा जा रहा है। सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे ने घोषणा की कि 'प्रेसिडेंट कप इंडिया' अब देश के अलग-अलग शहरों में साल में तीन बार आयोजित किया जाएगा। इससे खिलाड़ियों को लगातार बड़े मंच मिलेंगे और टेनिस क्रिकेट को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।

16 टीमों के बीच जोरदार मुकाबले

5 अप्रैल तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देशभर की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सैकड़ों खिलाड़ी अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं और हर दिन रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। टूर्नामेंट की विजेता टीम को 1 करोड़ रुपये और उपविजेता टीम को 50 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और अंडर-23 उभरते खिलाड़ी को आकर्षक बाइक दी जाएगी। वहीं 'मैन ऑफ द सीरीज' को महिंद्रा थार कार और हर मैच के 'मैन ऑफ द मैच' को 5,000 रुपये नकद और गिफ्ट प्रदान किए जाएंगे।

दर्शकों के लिए भी खास इनाम और रोमांचक शेड्यूल

आईटीसीएसएफ के महाराष्ट्र अध्यक्ष अभिजीत दरेकर के अनुसार, दर्शकों के लिए लकी ड्रॉ में तीन इलेक्ट्रिक बाइक जीतने का मौका है। साथ ही हर मैच के बाद 10,000 रुपये का कैश प्राइज और रिटेल वाउचर भी दिए जा रहे हैं। 2 और 3 अप्रैल को विभिन्न टीमों के बीच लीग मुकाबले होंगे, जबकि 5 अप्रैल को फाइनल खेला जाएगा।

ज्योति कालानी छात्रवृत्ति योजना पर भाजपा-शिंदे सेना में ठनी

डीबीडी संवाददाता | उल्हासनगर

उल्हासनगर महानगरपालिका के गलियारों में भाजपा और शिंदे सेना के बीच जारी 'दिखावे की दोस्ती' की परतें अब खुलने लगी हैं। 30 मार्च को बजट को लेकर हुई महासभा में स्वर्गीय ज्योति कालानी के नाम पर शुरू होने वाली छात्रवृत्ति योजना ने दोनों दलों के बीच ऐसी चिंगारी सुलगाई है, जो अब 'महा-संग्राम' का रूप ले चुकी है। शिंदे सेना और टीओके गठबंधन ने बजट में 7वीं से 12वीं तक की छात्राओं के लिए 500 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति योजना पेश की। विवाद तब शुरू हुआ जब इस योजना का नाम स्वर्गीय ज्योति कालानी रखने का प्रस्ताव दिया गया। भाजपा नगरसेवकों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए सदन में जमकर नारेबाजी और हंगामा किया।

महान विभूतियों को मिले सम्मान: भाजपा

भाजपा शहर अध्यक्ष राजेश वधारिया और नेता प्रदीप रामचंद्रानी का रुख साफ है। उनका कहना है कि सरकारी योजना का नाम माता सावित्रीबाई फुले या किसी अन्य राष्ट्रीय स्तर की महान विभूति के नाम पर होना चाहिए। भाजपा ने आरोप लगाया कि टीओके (TOK) काम कम और श्रेय लेने के लिए दिखावा ज्यादा करने के अवसर तलाशती है।

बजट लटका, गठबंधन पर मंडराए बादल

हंगामे और तीखे विरोध के कारण मार्च का महीना खत्म होने तक बजट पास नहीं हो सका। शहर में यह चर्चा जोरों पर है कि चुनाव से पहले एक-दूसरे के धुर विरोधी रहे ये दोनों दल सत्ता के लिए साथ तो आए, लेकिन इनके बीच वैचारिक तालमेल शून्य है। जानकारों का सवाल है—क्या यह गठबंधन अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगा?

महापौर ने दी स्थानीय सम्मान की दलील

महापौर अश्विनी कमलेश निकम ने स्वर्गीय ज्योति कालानी का बचाव करते हुए उन्हें एक 'डैसिंग' नेता बताया। उन्होंने कहा कि ज्योति कालानी ने विधायक और महापौर रहते हुए हमेशा छात्राओं के कल्याण की बात की थी। महापौर का तर्क है कि सावित्रीबाई फुले के नाम पर राज्य स्तर की योजना की मांग की जाएगी, लेकिन स्थानीय स्तर पर यह नाम सही है।

वर्ल्ड-क्लास स्टेडियम की तैयारी तेज़

प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग तुरंत पूरी करने के निर्देश

डीबीडी संवाददाता | नवी मुंबई

नवी मुंबई में वर्ल्ड-क्लास मॉडर्न स्टेडियम के निर्माण को लेकर राज्य सरकार ने प्रक्रिया तेज़ कर दी है। सांस्कृतिक कार्य और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आशीष शेलार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्टेडियम के लिए आवश्यक सभी योजनाएं जल्द पूरी की जाएं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि स्टेडियम के लिए स्थान तय करते समय कनेक्टिविटी, परिवहन व्यवस्था, पार्किंग सुविधा और अन्य आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि यह प्रोजेक्ट अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतर सके। इस परियोजना को लेकर मंत्रालय में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उरण विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेश बाल्दी और CIDCO के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू

प्रोजेक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इससे पहले साइट फाइनल करने और बेसिक प्लानिंग पूरी करने पर जोर दिया गया है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि मुख्य स्टेडियम के लिए करीब 40 एकड़ जमीन और पूरक सुविधाओं के लिए लगभग 30 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी।

अप्रैल मध्य तक प्रारंभिक रिपोर्ट पेश होगी

परियोजना की विस्तृत समीक्षा के लिए अप्रैल के मध्य तक एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद एक और समीक्षा बैठक आयोजित कर आगे की कार्ययोजना तय की जाएगी।

स्पोर्ट्स सिटी क्षेत्र पर विचार

नवी मुंबई के प्रस्तावित स्पोर्ट्स सिटी क्षेत्र में स्टेडियम बनाने के विकल्प पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों के अनुसार, इस क्षेत्र में लगभग 50 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण पहले ही किया जा चुका है। मंत्री शेलार ने निर्देश दिए कि बची हुई जमीन का अधिग्रहण चरणबद्ध तरीके से किया जाए, ताकि परियोजना में तेजी लाई जा सके और निर्माण कार्य समय पर शुरू हो सके।

ठाणेकरों ने दिया 878 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड प्रॉपर्टी टैक्स

मनपा पर हुई धनवर्षा

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

नए आर्थिक वर्ष की शुरुआत में ठाणे महानगरपालिका के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। वित्त वर्ष 2025-26 में मनपा ने रिकॉर्ड 878.37 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स एकत्र किया है। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में 810 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स एकत्र किया गया था। इस वर्ष अब तक 68.37 करोड़ अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि पर मेयर शर्मिला पिंपोलकर और आयुक्त सौरभ राव ने नागरिकों का आभार व्यक्त किया है।

915 करोड़ के लक्ष्य के करीब पहुंची मनपा

मनपा ने 2025-26 के लिए 915 करोड़ का लक्ष्य रखा था, जिसमें से लगभग 96 प्रतिशत की वसूली करने में सफलता मिली है। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए आयुक्त सौरभ राव के मार्गदर्शन में नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। उपायुक्त (प्रॉपर्टी टैक्स) जी.जी. गोदापुरे के अनुसार, इससे वसूली प्रक्रिया में तेजी आई।

जागरूकता अभियान से मिला फायदा

ऑटो रिक्शा, हाउसिंग सोसाइटी और मोबाइल वैन के जरिए जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही SMS के माध्यम से टैक्स भुगतान की याद दिलाई गई, जिससे नागरिकों की भागीदारी बढ़ी। समय पर टैक्स न भरने वालों के खिलाफ वारंट जारी कर संपत्ति जब्त करने, सेवाएं रोकने जैसी कार्रवाई भी की गई। इससे बकाया वसूली में तेजी आई।

डिजिटल और मल्टीपल पेमेंट विकल्पों पर जोर

मनपा ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देते हुए ऑनलाइन भुगतान के साथ-साथ कलेक्शन सेंटर पर चेक, डीडी, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई। जनवरी से मार्च 2026 के दौरान छुट्टियों में भी कलेक्शन सेंटर खुले रखे गए।

प्रभागवार कलेक्शन में माजीवडा-मानपाड़ा अव्वल

प्रभागवार कलेक्शन में माजीवडा-मानपाड़ा ने 236.51 करोड़ के साथ सबसे अधिक योगदान दिया। इसके अलावा वर्तकनगर 120.40 करोड़, नौपाड़ा-कोपरी 97.06 करोड़ और अन्य प्रभागों से भी वसूली हुई।

डिजिटल कलेक्शन में 87% से अधिक हिस्सा

मनपा ने टेक्नोलॉजी आधारित विकल्पों के जरिए टैक्स भुगतान को आसान बनाया। कुल कलेक्शन का 87.37% हिस्सा डिजिटल और अन्य आधुनिक माध्यमों से प्राप्त हुआ।

ठाणे एक्सप्रेसवे पर टेम्पो ड्राइवर की गुंडागर्दी

▸▸फ्यूल खत्म हुआ तो पुलिस से भिड़ा, लगा जाम

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

कोपरी ब्रिज पर सोमवार रात एक 22 वर्षीय टेम्पो ड्राइवर की 'लापरवाही' और बदतमीजी ने सैकड़ों मुसाफिरों की शाम आफत में डाल दी। बीच सड़क पर गाड़ी का ईंधन (फ्यूल) खत्म होने और फिर पुलिस से उलझने के कारण एक्सप्रेसवे पर एक घंटे का लंबा जाम लग गया। सोमवार रात जब मुंबई से ठाणे की ओर ट्रैफिक का भारी दबाव था, तभी कोपरी ब्रिज के पास एक टेम्पो का फ्यूल खत्म हो गया। गाड़ी ठीक सड़क के बीचों-बीच खड़ी हो गई। कोपरी पुल पर पहले से ही फ्लाईओवर का काम चलने की वजह से रास्ता संकरा (पतला) है, ऐसे में टेम्पो के रुकते ही देखते ही देखते गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं।

भारी वाहनों के लिए चेतावनी

ठाणे में चल रहे विकास कार्यों (मेट्रो, फ्लाईओवर) की वजह से सड़कें पहले से ही तंग हैं। ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि भारी वाहन चालक सड़क पर निकलने से पहले अपनी गाड़ी का फ्यूल, टायर और जरूरी दस्तावेज जरूर चेक करें, ताकि जनता को बेवजह जाम का सामना न करना पड़े।

बिना लाइसेंस के स्टीयरिंग पर कब्जा

पुलिस की जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। हंगामा कर रहे नसीम खान के पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था। बिना जरूरी कागजात और गाड़ी की कंडीशन चेक किए एक्सप्रेसवे पर उतरना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि दूसरों की जान के लिए भी खतरा है। ड्राइवर के अड़ियल रवैये को देखते हुए कोपरी पुलिस ने सख्त रुख अपनाया। नसीम के खिलाफ कोपरी पुलिस स्टेशन में सरकारी काम में बाधा डालने और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दिलीप पाटील ने साफ कर दिया है कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सहयोग के बजाय सीनाजोरी

जब ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुँची और जाम खुलवाने के लिए क्रेन मंगाकर टेम्पो हटाने की कोशिश की, तो ड्राइवर नसीम खान (22) ने पुलिस का साथ देने के बजाय उनसे बहस शुरू कर दी। उसने क्रेन लगाने में अड़ंगा डाला और पुलिसकर्मियों से बदतमीजी की, जिससे हालात और बिगड़ गए।

उल्हासनगर स्काईवॉक के नीचे नशे का कारोबार

▸▸700 ग्राम गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार

डीबीडी संवाददाता | उल्हासनगर

मध्यवर्ती पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कैंप-3 स्थित संजय गांधी नगर परिसर में स्काईवॉक के नीचे गांजा बेच रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से करीब 700 ग्राम गांजा जब्त किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि उक्त स्थान पर अवैध रूप से नशीले पदार्थों की बिक्री की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने देर रात मौके पर छापा मारकर आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया।

एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त सचिन गोरे के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। शहर के सभी आठ पुलिस थानों की सीमा में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है। पुलिस कांस्टेबल किशोर काले को मिली सूचना के आधार पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शंकर अवताडे और तुकाराम पदिर के नेतृत्व में करीब रात 1:30 बजे छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में सहायक पुलिस निरीक्षक राकेश शेवाले, पुलिस उपनिरीक्षक बाबासाहेब कोबर्ने, विलास मालशेट्टे सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे, जिन्होंने संयुक्त रूप से ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि जब्त किया गया गांजा आरोपी तक कैसे पहुंचा और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं। मामले की विस्तृत जांच जारी है।

नाली विवाद ने ली खूनी रंजिश की शक्ल

▸▸नशेड़ियों ने किया परिवार का जीना मुहाल

डीबीडी संवाददाता | भिवंडी

चाविंद्रा (नूरी नगर) इलाके से एक बेहद परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है, जहाँ एक छोटे व्यापारी का परिवार पिछले एक महीने से खौफ के साए में जीने को मजबूर है। नाली सफाई जैसे मामूली विवाद ने अब एक खतरनाक रंजिश का रूप ले लिया है, जिससे पूरा परिवार रात भर जागकर पहरा देने को मजबूर है। कपड़ा व्यापारी अनस साऊद आलम शेख के मुताबिक, यह सब पड़ोसियों के साथ नाली की सफाई को लेकर हुए एक छोटे से झगड़े से शुरू हुआ। लेकिन अब यह विवाद उनके परिवार की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है। आरोप है कि गुड्डू भंगारी, गोलू भंगारी, हंजला, इरफान, जैद और समीर जैसे लोग इस रंजिश को पालकर लगातार परिवार को निशाना बना रहे हैं।

दरवाजा पीटकर देते हैं जान से मारने की धमकी

पीड़ित परिवार का आरोप है कि ये बदमाश रोजाना देर रात नशे की हालत में डोंगर पाडा स्थित उनके घर पहुँचते हैं। वे न केवल जोर-जोर से दरवाजा पीटते हैं, बल्कि भद्दी गालियां देते हुए घर से बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी भी देते हैं। इस 'मानसिक प्रताड़ना' (Mental Torture) की वजह से परिवार के छोटे-छोटे बच्चे भी बुरी तरह सहमे हुए हैं।

पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल

हैरानी की बात यह है कि अनस शेख ने भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन में कई बार शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक बदमाशों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस की इसी ढिलाई की वजह से आरोपियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वे बेखौफ होकर रोज रात को दहशत फैला रहे हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि आरोपी अक्सर नशे की हालत में होते हैं, जिससे स्थिति कभी भी हिंसक मोड़ ले सकती है। पीड़ित परिवार का डर वाजिब है—यदि समय रहते इन पर लगाम नहीं कसी गई, तो यह मामूली विवाद किसी बड़ी अनहोनी में बदल सकता है।

जनरल बोर्ड में गूंजा मुद्दा, फिर भी अवैध निर्माण जारी

भू-माफियाओं के हौसले बुलंद

डीबीडी संवाददाता | भिवंडी

भिवंडी महानगरपालिका की जनरल बोर्ड सभा में गूँजने के बाद भी अवैध निर्माण का मुद्दा फाइलों में ही दबा नजर आ रहा है। भिवंडी महानगरपालिका की हालिया जनरल सभा में भाजपा नेता संतोष एम. शेट्टी ने पोगांव क्षेत्र में खाली जमीन पर हो रही अवैध प्लॉटिंग और दुकानों (गाला) के निर्माण का मुद्दा पूरी ताकत से उठाया था। उस वक्त उपायुक्त (अतिक्रमण) बिक्रम दराड़े ने सदन में भरोसा दिया था कि 3 दिन के भीतर पीला पंजा (बुलडोजर) चलेगा, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी ईंट से ईंट नहीं हिली है।

बीट निरीक्षकों की खामोशी

आयुक्त अनमोल सागर ने अवैध निर्माणों पर लगाम लगाने के लिए प्रभाग समिति क्रमांक-1 में तीन बीट निरीक्षकों—रमाकांत म्हात्रे, रवि जाधव और नितीन जामेकर की विशेष नियुक्ति की है। इसके बावजूद उनकी नाक के नीचे निर्माण कार्य जारी है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या ये अधिकारी जानबूझकर आंखें मूंदे हुए हैं? सूत्रों और स्थानीय चर्चाओं के मुताबिक, पोगांव का यह अवैध निर्माण एक स्थानीय रसूखदार नेता के इशारे पर हो रहा है। यही वजह मानी जा रही है कि उपायुक्त के आदेश के बाद भी संबंधित सहायक आयुक्त और जमीनी अमला कार्रवाई करने से कतरा रहा है। प्रशासन का यह डर या मिलीभगत शहर के सुनियोजित विकास के लिए बड़ा खतरा है।

291 अवैध निर्माणों का पुराना बोझ

भिवंडी मनपा पहले से ही पिछले एक साल में खड़े हुए 291 अवैध निर्माणों के मामले में कोर्ट और जनता के दबाव में है। ऐसे में नए निर्माणों पर तुरंत कार्रवाई न करना यह दर्शाता है कि प्रशासन पुराने अनुभवों से कोई सबक नहीं ले रहा है। निर्माण कार्य रुकने के बजाय और तेजी से बढ़ रहा है। जब इस देरी पर उपायुक्त बिक्रम दराड़े से दोबारा पूछा गया, तो उन्होंने फिर वही रटा-रटाया जवाब दिया कि निर्देश दिए जा चुके हैं और जल्द कार्रवाई होगी। लेकिन स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब तक हथौड़ा नहीं चलता, ऐसे बयानों पर भरोसा करना मुश्किल है।

इंडिगो के विमान में मिला 'डेंजर' लिखा टिश्यू पेपर

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

हवाई सफर के दौरान एक छोटी सी शरारत कितनी भारी पड़ सकती है, इसका एक बड़ा उदाहरण मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर देखने को मिला। दरअसल, अहमदाबाद के लिए उड़ान भरने को तैयार इंडिगो की एक फ्लाइट के अंदर 'डेंजर' लिखा हुआ एक टिश्यू पेपर बरामद हुआ। इसके बाद विमान को तुरंत रोक दिया गया।

लेबर कोड के खिलाफ मजदूरों का प्रदर्शन

- काली पट्टी बांधकर मनाया ब्लैक डे
- मुंबई सहित राज्यभर में विरोध प्रदर्शन

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

केंद्र सरकार के नए लेबर कोड के विरोध में बुधवार को मुंबई समेत महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में मजदूरों ने 'ब्लैक डे' मनाया। इस दौरान श्रमिकों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध दर्ज कराया। मजदूर संगठनों ने चेतावनी दी है कि जब तक कामगार विरोधी बताए जा रहे चारों लेबर कोड वापस नहीं लिए जाते, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। श्रमिकों का कहना है कि ये कानून उनके अधिकारों को कमजोर करते हैं।

प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों के विरोध को नजरअंदाज करते हुए 38 पुराने श्रम कानूनों को समाप्त कर चार नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं। इन कोड्स को लागू करने के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों की संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर यह आंदोलन किया गया। राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघ और महाराष्ट्र इंटक के नेतृत्व में बड़ी संख्या में श्रमिक सड़कों पर उतरे।

बंद फैक्ट्रियों के मजदूर भी हुए शामिल

मुंबई में पोद्दार, टाटा, इंदू नंबर 5 और दिग्विजय जैसी बंद फैक्ट्रियों के मजदूरों ने फैक्ट्री गेट पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इससे आंदोलन को व्यापक समर्थन मिला। चाकण, औरंगाबाद-वालुंज, रत्नागिरी, रायगढ़, नवी मुंबई और नाशिक सहित कई औद्योगिक क्षेत्रों में भी मजदूरों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई।

आंदोलन जारी रखने की चेतावनी

राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ और महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघ के अध्यक्ष व विधायक सचिन अहिर तथा महासचिव गोविंदराव मोहिते ने आंदोलन को सफल बताते हुए कहा कि जब तक चारों लेबर कोड वापस नहीं लिए जाते, तब तक किसी न किसी रूप में आंदोलन जारी रहेगा।

बाजार समितियों में 50 किलो से अधिक वजन पर रोक

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

राज्यभर में लागू होगा नया नियम

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की सभी कृषि उपज बाजार समितियों में शेतमाल (कृषि उपज) की बोरियों और पैकेटों का अधिकतम वजन 50 किलोग्राम निर्धारित करने का निर्णय लिया है। यह फैसला मजदूरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। यह निर्णय विश्व श्रम परिषद के दिशानिर्देशों और माथाडी (बोझा

ढोने वाले) मजदूरों की लंबे समय से लंबित मांग के आधार पर लिया गया है। इससे भारी वजन उठाने से होने वाली शारीरिक समस्याओं में कमी आने की उम्मीद है।

305 बाजार समितियों में होगी सख्ती

सरकार के अनुसार, राज्य की सभी 305 कृषि उपज बाजार समितियों में इस नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा, जिससे मजदूरों को सुरक्षित कार्य वातावरण मिल सके। वन मंत्री गणेश नाईक ने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाली उपज की बोरियां भी 50 किलो से अधिक न हों, इसके लिए केंद्र सरकार से देशव्यापी नियम बनाने का आग्रह किया जाएगा।

विपणन मंत्री ने दिए सख्त निर्देश

राज्य के विपणन मंत्री जयकुमार रावल ने सभी बाजार समितियों को इस आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, संबंधित विभाग को जल्द शासनादेश जारी करने को कहा गया है। माथाडी मजदूरों की मांग थी कि प्याज, आलू जैसी उपज की बोरियां 50 किलो से अधिक न भरी जाएं, ताकि उन्हें अधिक वजन उठाने से होने वाली शारीरिक परेशानी से राहत मिल सके। इस मुद्दे पर मंत्रालय में अहम बैठक भी आयोजित की गई।

वर्ली स्थित नेहरू सेंटर में प्रदर्शनी का आयोजन

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

मुंबई महानगरपालिका की ओर से वर्ली स्थित नेहरू सेंटर की आर्ट गैलरी में भव्य आर्ट एग्जिबिशन का आयोजन किया गया है। यह प्रदर्शनी 6 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें कला प्रेमियों की बड़ी संख्या उमड़ रही है। इस एग्जिबिशन में 35 कलाकारों की कुल 70 चयनित पेंटिंग्स को शामिल किया गया है। सभी चित्रों का चयन मनपा के शिक्षा विभाग की कला अकादमी द्वारा आयोजित आर्टिस्ट कैंप के माध्यम से किया गया है।

35 चित्रकारों की 70 चुनिंदा पेंटिंग्स प्रदर्शित

प्रकृति और धार्मिक स्थलों के दृश्य बने आकर्षण

प्रदर्शनी में महागणपति मंदिर पर पड़ती सुबह की किरणें, कृष्णा नदी के धुंध से ढके किनारे, पंचगनी की पहाड़ियों के मनमोहक दृश्य और पुराने मंदिरों के आसपास की शांति को खूबसूरती से चित्रित किया गया है, जो दर्शकों को खासा आकर्षित कर रहे हैं। राजेश्री शिरवाडकर ने कहा कि मनपा के आर्ट शिक्षकों ने प्रकृति को रंगों के जरिए जीवंत कर दिया है। इस तरह के आयोजनों से शिक्षकों की रचनात्मकता को नया मंच और पहचान मिलती है। कला अकादमी के प्रिंसिपल दिनकर पवार ने बताया कि आर्टिस्ट कैंप के जरिए कलाकारों को अपनी कल्पनाओं को कैनवास पर उतारने का अवसर मिलता है। इस पहल ने वाई, पंचगनी और आसपास के क्षेत्रों की सुंदरता को एक नई दृष्टि से प्रस्तुत किया है।

बुधवार को इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मनपा शिक्षा समिति की चेयरपर्सन राजेश्री शिरवाडकर ने किया। इस अवसर पर मनपा के कई अधिकारी और कला प्रेमी उपस्थित रहे। यह एग्जिबिशन 1 अप्रैल से 6 अप्रैल 2026 तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। शहरवासी यहां आकर विभिन्न कलाकृतियों का आनंद ले सकते हैं।

देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ महिला आरोपी गिरफ्तार

- घाटकोपर, अंधेरी और साकीनाका में चल रहा था नेटवर्क

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

मुंबई पुलिस ने बुधवार को घाटकोपर, अंधेरी और साकीनाका इलाकों में संचालित एक कथित देह व्यापार रैकेट का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने नेटवर्क चलाने वाली 38 वर्षीय महिला को हिरासत में लिया है और दो महिलाओं को शोषण से मुक्त कराया है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार महिला की पहचान कविता अनिल माने के रूप में हुई है, जो कांदिवली की निवासी है। आरोप है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को पैसों का लालच देकर उन्हें इस धंधे में धकेलती थी और ग्राहकों

को उनकी सेवाएं उपलब्ध कराती थी। घाटकोपर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 143(3) और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है।

पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि कविता माने विभिन्न होटलों में महिलाओं की आपूर्ति कर रही है। इसके बाद पुलिस ने एक 'नकली ग्राहक' के जरिए आरोपी से संपर्क किया। आरोपी ने कथित तौर पर ग्राहक को दो महिलाओं की तस्वीरें भेजीं।

30 हजार रुपए प्रति महिला की मांग

जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने प्रत्येक महिला के लिए 30,000 रुपए की मांग की थी। पुलिस ने इसी आधार पर जाल बिछाया और सौदा तय करने के बहाने उसे घाटकोपर-अंधेरी लिंक रोड स्थित एक लॉज में बुलाया।

नकली नोटों से बिछाया गया ट्रैप

आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए पुलिस ने नोटों के बंडल तैयार किए, जिनमें ऊपर असली 500 रुपए के नोट रखे गए थे, जबकि अंदर 'इंडियन चिल्ड्रन बैंक' लिखे नकली नोटों का इस्तेमाल किया गया। जैसे ही आरोपी ने पैसे लिए, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में बचाई गई महिलाओं ने बताया कि उन्हें प्रत्येक को 15,000 रुपए देने का वादा किया गया था।

मुंबई मनपा हुई मालामाल

7,610.90 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड वसूली

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

मुंबई महानगरपालिका (मनपा) ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मनपा ने निर्धारित लक्ष्य 7,341 करोड़ रुपए से अधिक 7,610 करोड़ 90 लाख रुपए का टैक्स संग्रह कर सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मनपा से मिली जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2026 को एक ही दिन में 399 करोड़ 74 लाख रुपए का राजस्व इकट्ठा कर नया रिकॉर्ड बनाया गया। इस उपलब्धि को मनपा की कर संग्रह प्रणाली की बड़ी सफलता माना जा रहा है।

मनपा आयुक्त अश्विनी भिड़े ने इस शानदार प्रदर्शन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए मजबूत वित्तीय संसाधन बेहद जरूरी होते हैं और प्रॉपर्टी टैक्स इसका प्रमुख स्रोत है। अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी के मार्गदर्शन में संयुक्त आयुक्त विश्वास शंकरवार और कलेक्टर गजानन बेल्लाले की देखरेख में विभाग ने बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए। साथ ही बड़े बकायादारों पर सख्ती और लगातार फॉलो-अप से वसूली तेज हुई। टैक्स भुगतान को आसान बनाने के लिए मनपा ने साप्ताहिक और सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खुले रखे। इसके साथ ही ऑनलाइन भुगतान की सुविधा को भी बढ़ावा दिया गया, जिससे नागरिकों को सहूलियत मिली।

103.68 प्रतिशत लक्ष्य हासिल

1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच मनपा ने कुल लक्ष्य का 103.68 प्रतिशत हासिल किया। यह प्रदर्शन पिछले वर्षों की तुलना में काफी बेहतर रहा है और इसे प्रशासनिक दक्षता का उदाहरण माना जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा मनपा ने अतिरिक्त जुर्माने के रूप में 301 करोड़ 13 लाख रुपए भी वसूले हैं।

महात्मा ज्योतिराव फुले की द्विशताब्दी जयंती वर्ष पर होंगे राज्यभर में कार्यक्रम

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को घोषणा की कि महात्मा ज्योतिराव फुले की द्विशताब्दी जयंती वर्ष के अवसर पर राज्यभर में वर्षभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह विशेष वर्ष 11 अप्रैल 2026 से 10 अप्रैल 2027 तक मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी द्विशताब्दी जयंती वर्ष समारोह के लिए गठित समिति की बैठक में दी। उन्होंने निर्देश दिया

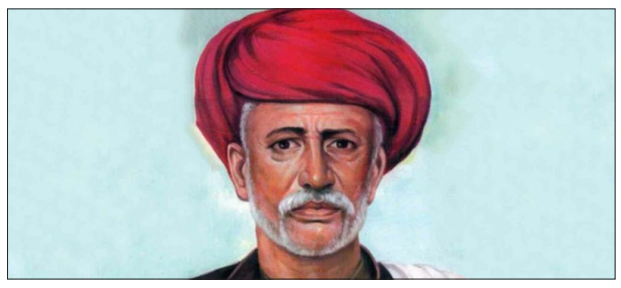

कि समिति से जुड़े प्रत्येक विभाग कम से कम दो से तीन कार्यक्रम आयोजित करें और 15 अप्रैल तक अपनी योजना प्रस्तुत करें।

फडणवीस ने बताया कि पुणे जिले के पुरंदर तहसील स्थित महात्मा फुले के मूल गांव खानवडी में जिला परिषद स्कूल का कायाकल्प किया गया है। इस द्विशताब्दी वर्ष की शुरुआत 11 अप्रैल को सीबीएसई शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस स्कूल के लोकार्पण से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि वर्षभर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए एक उपसमिति का गठन किया जाए, ताकि सभी गतिविधियां व्यवस्थित रूप से संचालित हो सकें।

फुले के साहित्य का होगा बहुभाषीय अनुवाद

उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिराव फुले के जीवन और कार्यों पर आधारित साहित्य का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक उनके विचार पहुंच सकें। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार सहित कई मंत्री उपस्थित रहे।

अनीता आडवाणी की याचिका खारिज

- राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्ते को शादी के तौर पर मान्यता देने का किया था अनुरोध

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को अभिनेत्री अनीता आडवाणी की याचिका खारिज कर दी। याचिका में उन्होंने दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना के साथ अपने संबंध को विवाह के रूप में मान्यता देने की मांग की थी। न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की एकल पीठ ने यह निर्णय सुनाया। आडवाणी ने वर्ष 2017 में दिंडोशी स्थित दीवानी न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनका मुकदमा तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया था। अनीता आडवाणी का कहना था कि वह और राजेश खन्ना उनकी मृत्यु (2012) तक लगभग एक दशक तक साथ रहे। उन्होंने यह भी दावा किया कि खन्ना ने उनके साथ गुप्त रूप से विवाह किया था। राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल कपाड़िया, बेटी ट्विंकल खन्ना और दामाद अक्षय कुमार ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। परिवार ने आडवाणी के विवाह और साथ रहने के दावे का लगातार विरोध किया है। आडवाणी ने यह भी आरोप लगाया कि राजेश खन्ना के निधन के बाद उन्हें उनके प्रसिद्ध बंगले 'आशीर्वाद' से जबरन बाहर कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने महिलाओं के घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून, 2005 के तहत मामला दर्ज कराया था। हालांकि, वर्ष 2015 में उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने इस कार्यवाही को रद्द कर दिया था। अदालत ने कहा था कि आडवाणी और खन्ना के बीच संबंध को कानून के तहत विवाह जैसा संबंध नहीं माना जा सकता।

मध्य रेल

शुद्धिपत्र अधिसूचना

27/03/2026 को प्रकाशित अधिसूचना को निम्नानुसार संशोधित किया गया है। निम्नलिखित पदों के लिए भर्ती हेतु 07/04/2026 को वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे।

पद का नाम	पद की योग्यताएं	साक्षात्कार की तिथि	पदों की संख्या
जीडीएमओ	एमबीबीएस	07/04/2026	1
रेडियोलॉजिस्ट	एमडी/डीएनबी डिग्री/डिप्लोमा इन रेडियो डायग्नोसिस। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तीन वर्षों का क्लिनिकल अनुभव अनिवार्य।	07/04/2026	1

CMP (Dental) के पद के लिए वॉक-इन इंटरव्यू रद्द माना जाए।

कुल 2 पद ओपन मार्केट और सेवानिवृत्त रेलवे, राज्य और केंद्रीय सरकार के डॉक्टरों के लिए, पूर्णकालिक अनुबंध आधार पर:

(A) ओपन मार्केट: अनुबंध की तिथि से एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिए, जिसे प्रति वर्ष आधार पर नवीनीकरण किया जा सकता है, जो 12 अवधियों से अधिक न हो या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या जब तक UPSC द्वारा चयनित डॉक्टर उपलब्ध न हो, जो भी पहले हो।

(B) सेवानिवृत्त डॉक्टर, रेलवे, राज्य और केंद्रीय सरकार के: अनुबंध की तिथि से एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिए, जिसे प्रति वर्ष आधार पर नवीनीकरण किया जा सकता है, जो 7 अवधियों से अधिक न हो, और 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या जब तक UPSC द्वारा चयनित डॉक्टर उपलब्ध न हो, जो भी पहले हो।

यहां उल्लिखित पदों को, प्रशासन की विवेकाधिकार पर, विशेषज्ञों की अनुपलब्धता की स्थिति में GDMOS (जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स) से भरा जा सकता है।

अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत रहेंगी। विस्तृत अधिसूचना के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं। www.cr.indianrailways.gov.in >About Us> Head Quarter > Personnel > Recruitment>Contract Medical Practitioners 01 of 2025

मेडिकल डायरेक्टर, चिकित्सा निर्देशक
भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
मेमोरियल अस्पताल, मध्य रेल

02

सुरक्षित यात्रा करें, फुटबोर्ड पर यात्रा न करें

पश्चिम रेलवे

प्रतिस्थापन कार्य

मंडल रेल प्रबंधक (WA), पश्चिम रेलवे, 6वीं मंजिल, इंजीनियरिंग विभाग, मुंबई सेंट्रल, मुंबई - 400 008 द्वारा ई-टेंडर सूचना संख्या: BCT/25-26/358 दिनांक 26.03.2026 आमंत्रित करते हैं। कार्य एवं स्थान: विरार कारशेड – विरार कारशेड में अत्यधिक जंग लगे रूफ वैली गटर एवं गैल्वाल्यूम शीट का प्रतिस्थापन। कार्य की अनुमानित लागत: ₹ 4,36,79,145.52, ईएमडी : ₹ 8,73,600/-, प्रस्तुति की तिथि एवं समय: 24.04.2026 को 15:00 बजे तक, खोलने की तिथि एवं समय: 24.04.2026 को 15:30 बजे, अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट: www.ireps.gov.in देखें. 1273

Like us on: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

एसी एवं वाटर कूलर मेंटेनेंस

Sr. DEE/RS/मुंबई सेंट्रल द्वारा ई-टेंडर संख्या: DRM-RS-2025-26-01-VR-R आमंत्रित करते हैं। कार्य का नाम: खराब/दोषपूर्ण पुर्जों की मरम्मत, बदलना तथा सफाई एवं रखरखाव कार्य, 'स्प्लिट एसी (2.0 टन क्षमता) एवं वाटर कूलर (40/80 लीटर क्षमता)' का SOR एवं कार्य क्षेत्र के अनुसार, EMU कारशेड विरार के विभिन्न स्थानों पर 2 वर्षों की अवधि के लिए। अनुमानित लागत: ₹ 2,62,504.29, बयाना राशि (EMD): ₹ 5,300/-, बोली शुरू होने की तिथि: 13.04.2026, टेंडर बंद होने की तिथि एवं समय: 27.04.2026 को 15:00 बजे, अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट: www.ireps.gov.in देखें. 1275

Like us on: facebook.com/WesternRly

मध्य रेल

एलएचबी कोच के सपोर्ट अरेंजमेंट में बदलाव

1. कार्य का नाम : एलएचबी कोच के फीडर जंक्शन बॉक्स के सपोर्ट अरेंजमेंट में बदलाव (संख्या : 480 कोच), 2. कार्य की अनुमानित कीमत : ₹ 45,30,746.88/-, 3. बयाना राशि: ₹ 90,615/-, 4. समाप्ती अवधि : 12 महीना, 5. निविदा भरने का अंतिम दिन और समय : दिनांक 22/04/2026 दोपहर 12 बजे तक। 6. ऑफर की वैधता : 60 दिन। निविदाएं केवल ई-निविदा प्रारूप में वेबसाइट www.ireps.gov.in के माध्यम से स्वीकार की जाएंगी। निविदा दस्तावेज वेबसाइट पर उपलब्ध है। ई-निविदा सूचना क्र. पीजी_डीटीएल_710.

03

सुरक्षित यात्रा करें, फुटबोर्ड पर यात्रा न करें

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

(हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग विभाग)

ई-निविदा सूचना

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बी.एम.सी.) के आयुक्त द्वारा नीचे दिए गए कार्य हेतु पैकेट - 'A', 'B' एवं 'C' प्रणाली में प्रतिशत दर के आधार पर ई-टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं :-

विभाग	हाइड्रोलिक इंजीनियर
उप विभाग	ई.ई.डब्ल्यू.डब्ल्यू. (सिविल) मेंटेनेंस
टेंडर संदर्भ आईडी	2026_MCGM_1289689
विषय	'N' वार्ड के कामा लेन स्थित घाटकोपर म्युनिसिपल वाटर वर्क्स यार्ड परिसर में ए.ई. (एम.डब्ल्यू.) ई.एस. के अंतर्गत घाटकोपर मीटर वर्कशॉप नामक भवन की संरचनात्मक एवं सामान्य मरम्मत कार्य।
टेंडर बिक्री	02/04/2026 को 11:00 बजे से 08/04/2026 को 16:00 बजे तक
प्रस्तुति की अंतिम तिथि	08/04/2026 को 16:00 बजे तक
प्री-बिड बैठक	लागू नहीं
पैकेट A खोलना (ऑनलाइन)	10/04/2026 को 16:00 बजे के बाद
पैकेट B खोलना (ऑनलाइन)	10/04/2026 को 16:15 बजे के बाद
पैकेट C खोलना (ऑनलाइन)	22/04/2026 को 15:00 बजे के बाद
वेबसाइट	http://mahatenders.gov.in
संपर्क अधिकारी :	
A) नाम	श्री एस. एम. राठोड, उप अभियंता डब्ल्यू.डब्ल्यू. (सिविल) मेंटेनेंस; श्री ए. ए. खान, सहायक अभियंता डब्ल्यू.डब्ल्यू. (सिविल) मेंटेनेंस
B) दूरभाष (कार्यालय)	022 25126376
C) मोबाइल नंबर	9867593724; 9867796184
D) ईमेल आईडी	eewwcivilmaintes.he@mcgm.gov.in

पीआरओ/07/विज्ञा./26-27

हस्ता/
उप हाइड्रोलिक इंजीनियर (मेंटेनेंस)

हल्का बुखार होने पर डॉक्टर से मिलें।

संपादकीय

ट्रंप का एग्जिट प्लान

28 फरवरी, 2026 को शुरू हुआ इस्राइल-अमेरिका और ईरान का युद्ध अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कि अमेरिका जल्द ही इस युद्ध से बाहर निकल सकता है। विशेष रूप से उनका यह संकेत कि 'होर्मुज जलडमरूमध्य' को खुलवाए बिना ही युद्ध विराम किया जा सकता है, अमेरिकी रणनीतिकारों के लिए एक असहज स्थिति पैदा करता है। यह न केवल युद्ध के उद्देश्यों पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आधुनिक युद्ध केवल मिसाइलों की संख्या से नहीं, बल्कि आर्थिक और भू-राजनीतिक दबाव से जीते या हारे जाते हैं। आंकड़ों के नजरिए से देखें तो अमेरिका और ईरान के बीच कोई मुकाबला ही नहीं है। 'ग्लोबल फायरपावर रैंकिंग 2026' में नंबर एक पर काबिज अमेरिका का रक्षा बजट ईरान से लगभग 100 गुना अधिक है। जहां अमेरिका के पास 13,000 से अधिक उन्नत विमान और 11 विमानवाहक पोत हैं, वहीं ईरान के पास पुराने सोवियत युग के संसाधन हैं। लेकिन युद्ध के मैदान में यह भारी अंतर तब धुंधला पड़ गया जब ईरान ने अपने भूगोल को ही हथियार बना लिया। होर्मुज जलडमरूमध्य, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, उसे बाधित करके ईरान ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की नब्ज पकड़ ली है। कच्चे तेल की कीमतों का 100 डॉलर प्रति बैरल के पार जाना और अमेरिकी घरेलू बाजार में पेट्रोल की बढ़ती कीमतें ट्रंप प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई हैं। ईरान की रणनीति इस युद्ध को जीतने की नहीं, बल्कि इसमें टिके रहने की रही है। उसने 'असममित युद्ध' का सहारा लेते हुए अपने सस्ते लेकिन प्रभावी ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए अमेरिका के क्षेत्रीय सहयोगियों और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। इसके साथ ही, ईरान ने पश्चिम एशिया में स्थित अमेरिकी टेक कंपनियों के डाटा सेंटर्स पर हमले की जो धमकी दी है, उसने युद्ध को पारंपरिक सीमा से निकालकर डिजिटल और आर्थिक सुरक्षा के दायरे में खड़ा कर दिया है। अमेरिका के लिए दुविधा यह है कि उसके पास ईरान के खर्ग द्वीप जैसे रणनीतिक ठिकानों को तबाह करने की क्षमता तो है, लेकिन इसकी राजनीतिक और मानवीय कीमत बहुत अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का 'एग्जिट प्लान' उनकी घरेलू राजनीति और आगामी चुनावों से प्रेरित है। अमेरिकी जनता महंगाई और युद्ध के खर्च से त्रस्त हो रही है। 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' में अमेरिका अब तक लगभग 850 टॉमहॉक मिसाइलें दाग चुका है, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 20 लाख डॉलर है। इसके अलावा, 20 से अधिक विमानों का नुकसान और अरबों डॉलर का युद्ध खर्च अमेरिका की सैन्य क्षमता के भंडार को चीन जैसे अन्य बड़े खतरों के प्रति संवेदनशील बना रहा है। ट्रंप अब 'मिशन पूरा होने' का दावा करके सम्मानजनक वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं, भले ही रणनीतिक रूप से होर्मुज का संकट हल न हुआ हो। अंततः, यह युद्ध इस बात का गवाह है कि सैन्य ताकत लड़ाइयां तो जीत सकती है, लेकिन दीर्घकालिक दबाव और भौगोलिक लाभ युद्ध के अंतिम नतीजे तय करते हैं। यदि अमेरिका होर्मुज को मुक्त कराए बिना पीछे हटता है, तो इसे ईरान की रणनीतिक जीत और अमेरिका की एक बड़ी नाकामी के रूप में देखा जाएगा। यह संघर्ष वैश्विक शक्तियों को यह सबक देता है कि वैश्वीकरण के इस दौर में आर्थिक अंतर्संबंध किसी भी घातक हथियार से ज्यादा मारक साबित हो सकते हैं। आने वाले दो-तीन हफ्ते यह तय करेंगे कि क्या यह वास्तव में शांति की ओर एक कदम है या पश्चिम एशिया में एक और अस्थिर अध्याय की शुरुआत।

शख्सियत

बिंदेश्वर पाठक

स्वच्छता और मानवीय गरिमा के मसीहा

भारत के सामाजिक सुधार के इतिहास में डॉ. बिंदेश्वर पाठक का नाम एक ऐसे महापुरुष के रूप में अंकित है, जिन्होंने समाज के सबसे वंचित और तिरस्कृत वर्ग की पीड़ा को न केवल समझा, बल्कि उसे दूर करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्हें 'सुलभ इंटरनेशनल' के संस्थापक और भारत में स्वच्छता क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है।

उनका जीवन इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति की दृढ़ इच्छाशक्ति करोड़ों लोगों के जीवन में सम्मान और स्वच्छता की रोशनी ला सकती है। बिंदेश्वर पाठक का जन्म 2 अप्रैल, 1943 को बिहार के वैशाली जिले के एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके जीवन की दिशा तब बदली जब वे एक गांधीवादी शोध संस्थान से जुड़े। वहां उन्हें मैला ढोने वाली प्रथा (की अमानवीय वास्तविकता का अनुभव हुआ। उन्होंने देखा कि कैसे समाज का एक वर्ग सिर पर गंदगी ढोने को मजबूर है और उन्हें अछूत माना जाता है। इस सामाजिक बुराई ने उनके अंतर्मन को झकझोर दिया और उन्होंने शपथ ली कि वे इस कुप्रथा को जड़ से मिटाकर रहेंगे। 1970 में डॉ. पाठक ने 'सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन' की स्थापना की। उनका लक्ष्य केवल शौचालय बनाना नहीं था, बल्कि मानवीय गरिमा को पुनः स्थापित करना था। उन्होंने 'सुलभ शौचालय' के रूप में एक ऐसी तकनीक विकसित की जो कम लागत वाली और पर्यावरण के अनुकूल थी। इससे न केवल खुले में शौच की समस्या का समाधान हुआ, बल्कि मैला ढोने वाले हजारों लोगों को इस अपमानजनक कार्य से मुक्ति मिली। उनके द्वारा बनाए गए सार्वजनिक शौचालयों ने शहरी स्वच्छता की परिभाषा बदल दी। डॉ. पाठक का कार्य केवल तकनीक तक सीमित नहीं था। वे एक सच्चे समाज सुधारक थे। उन्होंने मैला ढोने वाले परिवारों के बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के कौशल विकास के लिए कई संस्थान खोले। उन्होंने राजस्थान के टोंक और अलवर जैसे शहरों में उन महिलाओं को सम्मान दिलाया जो कभी अछूत मानी जाती थीं। उन्हें मंदिरों में प्रवेश कराया, ब्राह्मणों के साथ भोजन कराया और उन्हें मुख्यधारा के समाज से जोड़ा। उनका मानना था कि असली स्वच्छता केवल गलियों की नहीं, बल्कि समाज की सोच की होनी चाहिए। डॉ. पाठक के नवाचारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। संयुक्त राष्ट्र (UN) और विश्व बैंक जैसे संगठनों ने उनके 'सुलभ मॉडल' को विकासशील देशों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा, उन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज और एनर्जी ग्लोब अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सम्मान भी मिले। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क ने भी उनके कार्यों के सम्मान में 14 अप्रैल को 'बिंदेश्वर पाठक दिवस' घोषित किया था। 15 अगस्त, 2023 को डॉ. बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी 'स्वच्छ भारत अभियान' के रूप में जीवित है। उन्होंने सिखाया कि समाज में बदलाव लाने के लिए केवल आलोचना करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जमीन पर उतरकर समाधान खोजना पड़ता है। डॉ. बिंदेश्वर पाठक का जीवन हमें सिखाता है कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता यदि वह मानवता की सेवा के लिए किया जाए। उन्होंने गंदगी को साफ करने वाले हाथों को सम्मान दिलाया और भारत को एक स्वच्छ एवं समावेशी राष्ट्र बनाने की दिशा में अभूतपूर्व योगदान दिया।

विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस

समावेशी भारत की चुनौतियां और संभावनाएं

डॉक्टर बबलू सोनकर
प्रांतीय चिकित्सा सेवा
उत्तर प्रदेश

हम समझते हैं कि ऑटिज्म के प्रति जागरूकता केवल 1 दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाला अभियान होना चाहिए। हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जहां ऑटिज्म से प्रभावित व्यक्ति को दया की नहीं, बल्कि अवसर और सम्मान की नजर से देखा जाए। जब हम उनके 'अलग होने' को उनकी 'शक्ति' के रूप में स्वीकार करेंगे, तभी भारत सही मायनों में एक समावेशी राष्ट्र बन पाएगा।

हर साल 2 अप्रैल को 'विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस' के रूप में मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य 'ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर' (ASD) से जूझ रहे व्यक्तियों के प्रति समाज में संवेदनशीलता और स्वीकार्यता बढ़ाना है। ऑटिज्म कोई मानसिक बीमारी नहीं, बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो व्यक्ति के संचार कौशल और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करती है। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में, जहां विविधता ही पहचान है, ऑटिज्म से प्रभावित करोड़ों लोगों को मुख्यधारा में शामिल करना एक बड़ी मानवीय और सामाजिक जिम्मेदारी है। भारत में ऑटिज्म की वर्तमान दशा अत्यंत चिंताजनक और चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। विभिन्न शोधों के अनुसार, भारत में लगभग 1:68 का अनुपात है, यानी हर 68 बच्चों में से 1 बच्चा ऑटिज्म से प्रभावित है। इसका अर्थ है कि देश में करीब 18,000,000 से 20,000,000 (1.8 से 2 करोड़) लोग इस स्थिति के साथ जी रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जागरूकता के अभाव में आज भी ऑटिज्म का निदान (Diagnosis) बहुत देरी से होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे अक्सर ऊपरी हवा या बच्चे का जिद्दीपन समझ लिया जाता है, जिससे प्रारंभिक हस्तक्षेप (Early Intervention) का कीमती समय हाथ से निकल जाता है। एक डॉक्टर के नाते मैं देखता हूं कि जब तक बच्चा विशेषज्ञ के पास पहुंचता है, तक तक उसके विकास के कई महत्वपूर्ण चरण बीत चुके होते हैं। चिकित्सा विज्ञान के नजरिए से, ऑटिज्म का कोई स्थायी इलाज या 'दवा' नहीं है, लेकिन सही समय पर दी गई थेरेपी बच्चे के जीवन की गुणवत्ता में जमीन-आसमान का अंतर ला सकती है। हमें यह समझना होगा कि ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति का मस्तिष्क केवल अलग तरीके से 'वायर्ड' होता है। उनकी संवेदी प्रक्रियाएं (Sensory Processing) हमसे भिन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक सामान्य शोर भी उनके लिए असहनीय हो सकता है। समाज में इस वैज्ञानिक तथ्य की समझ विकसित करना अनिवार्य है ताकि इन बच्चों को 'विचित्र' या 'अनुशासनहीन' कहने के बजाय उन्हें सही सहयोग और धैर्य प्रदान किया जा सके।

हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में भारत की दिशा में सकारात्मक बदलाव आए हैं। 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016'

के तहत ऑटिज्म को एक विशिष्ट दिव्यांगता के रूप में मान्यता देना एक क्रांतिकारी कदम रहा है। इससे प्रभावित व्यक्तियों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण के साथ-साथ कानूनी संरक्षण भी प्राप्त हुआ है। सरकार द्वारा जारी UDID (स्वावलंबन कार्ड) और 'निरामय' जैसी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को एक संबल प्रदान किया है, जिससे वे थेरेपी और उपचार की ओर कदम बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन कानून का लाभ तभी मिल सकता है जब परिवार जागरूक हों और व्यवस्था पारदर्शी हो। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए भारत को अपने स्वास्थ्य और शिक्षा ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। सबसे पहली आवश्यकता सस्ती और सुलभ थेरेपी की है; वर्तमान में स्पीच और ऑक्यूपेशनल थेरेपी जैसी सुविधाएं इतनी महंगी हैं कि मध्यमवर्गीय परिवार भी इनका खर्च नहीं उठा पाते। साथ ही, हमें हर जिले में 'प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र' स्थापित करने होंगे ताकि 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों की पहचान कर उनका उपचार शुरू किया जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में भी 'समावेशी स्कूलों' की कमी को दूर करना होगा ताकि ये बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सकें। एक चिकित्सक के रूप में मेरा सुझाव है कि मेडिकल पाठ्यक्रम में भी ऑटिज्म पर विशेष मॉड्यूल जोड़े जाएं ताकि सामान्य प्रैक्टिसनर्स भी इसे शुरुआती स्तर पर पहचान सकें। आंकड़ों और सामाजिक सुधार के लिए कुछ ठोस सुझावों पर अमल करना अनिवार्य है। सरकार को हर ब्लॉक स्तर पर ऑटिज्म स्क्रीनिंग को अनिवार्य बनाना चाहिए और डॉक्टरों के साथ-साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना चाहिए। कॉर्पोरेट जगत को 'न्यूरोडायवर्सिटी' को बढ़ावा देते हुए ऑटिज्म प्रभावित वयस्कों के लिए विशेष रोजगार के अवसर सृजित करने चाहिए, क्योंकि उनमें डेटा और तकनीकी कार्यों के लिए अद्भुत एकाग्रता होती है। इसके अलावा, माता-पिता के लिए 'काउंसलिंग सेंटर' बनाना भी जरूरी है ताकि वे इस लंबी लड़ाई में मानसिक रूप से मजबूत रह सकें। हमें उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि उनका बच्चा समाज पर बोझ नहीं, बल्कि एक अलग प्रतिभा का धनी नागरिक है। हम समझते हैं कि ऑटिज्म के प्रति जागरूकता केवल 1 दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाला अभियान होना चाहिए। हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जहां ऑटिज्म से प्रभावित व्यक्ति को दया की नहीं, बल्कि अवसर और सम्मान की नजर से देखा जाए। जब हम उनके 'अलग होने' को उनकी 'शक्ति' के रूप में स्वीकार करेंगे, तभी भारत सही मायनों में एक समावेशी राष्ट्र बन पाएगा। 2 अप्रैल का यह दिन हमें याद दिलाता है कि हर मस्तिष्क अलग होता है और हर व्यक्ति के पास समाज को देने के लिए कुछ न कुछ विशेष अवश्य है। आइए, एक डॉक्टर के संकल्प और एक नागरिक के कर्तव्य के साथ हम मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां कोई भी बच्चा पीछे न छूटे।

हमारी गीता

श्रेय और प्रेय

स्वामिनी निष्कलानंदा
चिन्मय मिशन कल्याण

हमारे जीवन के दो प्रकार के ध्येय होते हैं—श्रेय और दूसरा प्रेय। जितने भी ध्येय हैं, वे सभी इन दोनों में समाए हैं। प्रेय का अर्थ है—जो सुखकर है। प्रेय दिखने वाला है और अपने कर्म से प्राप्त होता है। जैसे घर, गाड़ी इत्यादि हमें चाहिए तो पैसों से खरीद सकते हैं, और पैसे हम कष्ट करके कमा सकते हैं। परंतु जितना पैसा या श्रम, उतना ही सुख—यही प्रेय है। अर्थात प्रेय सीमित है, क्षणिक है। जो उत्पन्न हुआ है, उसका नाश अवश्य है। जो नाशवान है, वह अखंड सुख दे नहीं सकता। दूसरी बात, सुख तो मिलेगा, परंतु उसके साथ दुःख समाप्त नहीं होता। प्रेय बदलता रहता है। साइकिल से ज्यादा स्कूटर में और स्कूटर से ज्यादा मोटरकार में सुख लगता है। वस्तुएं बदलती रहती हैं, परंतु सुख हाथ में आता ही नहीं। प्रेय यह ध्येय न होकर ध्येय का साधन है। साधन के बिना साध्य नहीं। प्रेय साधन है, फिर भी शास्त्र प्रेय को भी ध्येय बताते हैं। असली ध्येय श्रेय है। श्रेय जो दिखता नहीं है, जो अमर्याद, अनंत और शाश्वत है। जो कर्म का फल नहीं है और जो इस जीवन के बाद भी रहता है। श्रेय आत्मसुख है, आत्मवैभव और आत्मज्ञान है। श्रेय धर्म-अधर्म के भी परे है। धर्म-अधर्म का फल पुण्य-पाप है, परंतु श्रेय इन पाप-पुण्यों के भी परे है। पुण्य-पाप भी शाश्वत नहीं हैं। धर्म अर्थात विधि (कुछ करना) और निषेध (कुछ नहीं करना) है, परंतु क्या करना और क्या नहीं करना—यह दिखाने वाली, उससे भी परे रहने वाली ज्ञान-दृष्टि है। कोई नृत्य, गायन सीखता है तो नाचकर, गाकर वह दिखा सकता है। क्रिकेट, बॉक्सिंग, चित्रकला—ये सब दिखाए जा सकते हैं। परंतु सत्य, दया, करुणा जैसे जीवन-मूल्य कोई दिखा नहीं सकता। विश्व-

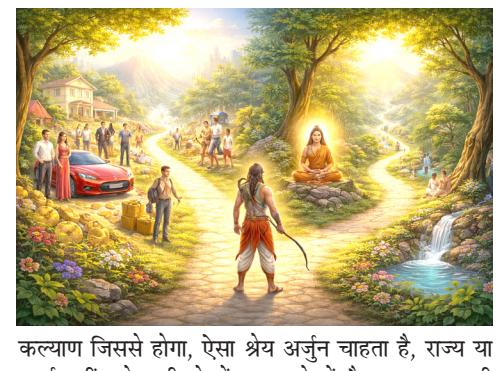

कल्याण जिससे होगा, ऐसा श्रेय अर्जुन चाहता है, राज्य या स्वर्ग नहीं। श्रेय जीतने में या हारने में है—यह वह अभी जानता नहीं।

जीवन ऊर्जा

आधुनिक यूरोप के पितामह, कार्ल महान (शारलेमेन) का जन्म संभवत: 2 अप्रैल, 747 को हुआ था। उस दौर में जब पश्चिमी यूरोप बिखरा हुआ था, उन्होंने अपनी अदम्य वीरता और दूरदर्शिता से एक विशाल साम्राज्य को सूत्रबद्ध किया। वे न केवल एक अपराजेय योद्धा थे, बल्कि उन्होंने मध्यकालीन यूरोप में शिक्षा, कला और न्याय व्यवस्था के पुनर्जागरण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। 28 जनवरी, 814 को उनके निधन के साथ एक महान युग का अंत हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी यूरोपीय एकता और संस्कृति के प्रतीक रूप में मौजूद है!

कार्ल महान (शारलेमेन) : जन्म : 2 अप्रैल 747

जन्म

धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं

दूसरी भाषा का ज्ञान होना, दूसरी आत्मा प्राप्त करने के समान है। शिक्षा ही वह नींव है जिस पर सभ्य समाज और मजबूत साम्राज्य टिका होता है। बिना ज्ञान के कर्म अंधा है, और बिना कर्म के ज्ञान व्यर्थ है। पुस्तकों का संचय करना केवल शौक नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकाश स्तंभ बनाना है। सच्चा विद्वान वही है जो अपने ज्ञान का उपयोग न्याय और शांति के लिए करे। अज्ञानता वह अंधकार है जिसे केवल शिक्षा की मशाल से ही मिटाया जा सकता है। बुद्धिमान शासक वह है जो तलवार से पहले कलम की शक्ति को समझता है। एक राजा का कर्तव्य केवल युद्ध जीतना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के जीवन को सुरक्षित और समृद्ध बनाना है। अनुशासन ही वह सेतु है जो कल्पना और उपलब्धि को जोड़ता है। यदि आप दूसरों पर शासन करना चाहते हैं, तो पहले स्वयं की इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। न्याय में देरी करना, न्याय को नकारने के समान है। एक विशाल साम्राज्य का भार केवल वही उठा सकता है जिसके कंधे सत्य और धर्म पर टिके हों। कानून ऐसा होना चाहिए जिसे साधारण से साधारण व्यक्ति भी समझ सके और उसका पालन कर सके। शक्ति का दुरुपयोग करना कायरता है, जबकि शक्ति का उपयोग कमजोरों की रक्षा के लिए करना वीरता है। मैदान से भागने

वाले योद्धा से बेहतर वह है जो गौरव के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो। असंभव शब्द केवल उनके लिए है जो प्रयास करने से पहले ही हार मान लेते हैं। संकल्प की दृढ़ता ही एक साधारण मनुष्य को सम्राट बनाती है। जीत का स्वाद तभी मीठा होता है जब वह कठिन परिश्रम और ईमानदारी से हासिल की गई हो। डरना बुरा नहीं है, लेकिन डर के आगे घुटने टेक देना सबसे बुरा है। एक महान सेना वही है जिसका नेतृत्व एक महान उद्देश्य के साथ किया जाए। ईश्वर की सेवा का अर्थ है—उसके द्वारा बनाई गई मानवता की सेवा करना।

सर्वसिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ बिजाना शाजापुर मध्यप्रदेश

प्रकाण्ड विद्वान अष्टावक्र

भारतीय ज्ञान परंपरा में कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं, जो समय और परिस्थितियों की सीमाओं को पार कर मानवता को शाश्वत सत्य का मार्ग दिखाते हैं। ये महापुरुष हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची महानता न तो शरीर की सुंदरता में है और न ही आयु के अनुभव में, बल्कि वह ज्ञान, विवेक और आत्मबोध में निहित होती है। अष्टावक्र ऐसे ही विलक्षण ऋषि थे, जिनका जीवन केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि गहन दार्शनिक चेतना का प्रतीक है। उनका व्यक्तित्व यह संदेश देता है कि यदि मनुष्य के भीतर सत्य की खोज की तीव्र जिज्ञासा हो, तो वह हर बाधा को पार कर सकता है। अष्टावक्र का नाम ही उनके जीवन का परिचय देता है— 'आठ स्थानों से वक्र', अर्थात जिनका शरीर आठ स्थानों से टेढा था। पौराणिक कथा के अनुसार, वे गर्भ में ही इतने विद्वान थे कि अपने पिता कहोड को अशुद्ध वेदपाठ करते सुनकर उन्होंने उन्हें टोक दिया। यह घटना उनकी असाधारण बुद्धि और सत्य के प्रति अडिग निष्ठा को दर्शाती है। हालांकि इस साहस का परिणाम उन्हें श्राप के रूप में मिला और उनका शरीर वक्र हो गया, परंतु यह वक्रता उनके ज्ञान के प्रकाश को कभी मंद नहीं कर सकी। अष्टावक्र के पिता कहोड एक बार मिथिला के राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ के लिए गए, जहां बंदी नामक विद्वान से पराजित होकर उन्हें जल में डुबो दिया गया। उस समय अष्टावक्र का जन्म भी नहीं हुआ था। जब वे बड़े हुए और उन्हें अपने पिता के साथ घटित घटना का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने अपने मामा श्वेतकेतु के साथ जनक की सभा में जाने का निश्चय किया। यह निर्णय केवल एक पुत्र का कर्तव्य नहीं था, बल्कि ज्ञान और सत्य की प्रतिष्ठा के लिए उठाया गया साहसिक कदम था।

राजा जनक की सभा में जब द्वारपालों ने उन्हें बालक समझकर रोकना चाहा, तब अष्टावक्र ने अत्यंत प्रभावशाली शब्दों में कहा कि मनुष्य की महानता उसकी आयु से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान और बुद्धि से आंकी जाती है। उनके इस उत्तर ने वहां उपस्थित सभी को चकित कर दिया। राजा जनक ने भी उनकी प्रतिभा को परखने के लिए अनेक गूढ़ प्रश्न किए, जिनका अष्टावक्र ने अत्यंत सरल और तार्किक उत्तर देकर सभी को प्रभावित कर दिया। अंततः उनका बंदी के साथ शास्त्रार्थ हुआ, जो अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक था। इसमें एक से तेरह तक के संख्यात्मक और दार्शनिक तत्त्वों का अद्भुत वर्णन हुआ। अष्टावक्र ने अपनी प्रखर बुद्धि और तर्कशक्ति से बंदी को पराजित कर दिया। इस विजय के परिणामस्वरूप उनके पिता सहित अन्य ब्राह्मण भी पुनः जीवित होकर सभा में लौट आए। यह केवल एक व्यक्तिगत विजय नहीं थी, बल्कि सत्य और ज्ञान की विजय थी। पिता के निर्देश पर अष्टावक्र ने समंगा नदी में स्नान किया, जिससे उनके शरीर की वक्रताएं समाप्त हो गईं। किंतु उनका वास्तविक स्वरूप उनके शरीर में नहीं, बल्कि उनके ज्ञान और आत्मबोध में था। आगे चलकर उन्होंने अद्वैत वेदान्त के गूढ़ सिद्धांतों को 'अष्टावक्र गीता' के माध्यम से व्यक्त किया, जो आज भी आत्मज्ञान का एक अनुपम ग्रंथ मानी जाती है। अष्टावक्र का जीवन हमें यह सिखाता है कि बाहरी रूप, शारीरिक सीमाएं या सामाजिक परिस्थितियां किसी भी व्यक्ति की वास्तविक पहचान नहीं होतीं। सच्ची पहचान उसके विचारों, ज्ञान और आत्मिक ऊंचाई में निहित होती है।

पंडित कैलाशचंद्र शर्मा
वैदिक सनातन संस्कृति के प्रचारक व सर्व सिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ के संस्थापक।
मो. नं. 9425980556

अपने विचार

पिछले हफ्ता मीडिया से बात करते हुए मैने नेहरु गांधी परिवार के कारनामों के क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भआदरणीय बीजू पटनायक जी के संदर्भ में मेरी बातों से गलत अर्थ निकाला गया ।बीजू बाबू हमारे लिए हमेशा ऊंचे कद के स्टेट्समैन रहे हैं और रहेंगे ।

-निशिकांत दुबे
नेता, भाजपा

आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस-नीत यूडीएफ का एजेंडा सिर्फ एलडीएफ के 10 साल के शासन के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा सकारात्मक है ।एलडीएफ राज्य सरकार सितंबर तक पैसे खत्म कर देती है और फिर उधार लेकर भुगतान करना पड़ता है।

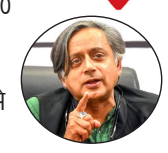

-शशि थरूर
नेता, कांग्रेस

सरकारी खजाना खाली है और जो बचा हुआ है उसे भ्रष्ट अधिकारी समेट लेंगे। जदयू-भाजपा ने फिर पलटी मारी। चुनावों के वक्त मुफ़्त 125 यूनिट फ़्री बिजली देने का वादा कर चीटर मीटर वाले महज 4 महीने में ही जनता को लूटने वाले अपने असल रंग में लौट आए।

-तेजस्वी यादव
अध्यक्ष, राजद

हम जो देख रहे हैं वह बेहद चिंताजनक है। इस बात के उत्तरोत्तर संकेत मिल रहे हैं कि बंगाल की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने के समन्वित प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके केंद्र में भाजपा है और निर्वाचन आयोग आंखें मूंदे हुए है।

-अभिषेक बनर्जी
नेता, टीएमसी

अपने विचार

डीबीडी कार्यालय

ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के.के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई-400001
indiagroundreport@gmail.com
भेज सकते हैं।

यह अखबार "माध्यम कार्पोरेट सर्विसेज लि." के लिए प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक अरुण लाल द्वारा ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के. के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001 से प्रकाशित एवं सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नं. 4, एन.के.इंडस्ट्रियल इस्टेट, इनसाइड प्रवासी इंडिस्ट्रयल इस्टेट गेट नं. 2, गोरेगांव पू., मुंबई-63 से मुद्रित. फोन नं. 022-66555719 ईमेल : indiagroundreport@gmail.com कार्यकारी संपादक : अमित बृज (पी.आर.बी. अधिनियम के अंतर्गत खबरों के चयन के लिए ज्मिेदार).

ब्रीफ न्यूज़

उज्जैन में शिव-शक्ति साधना शिविर का आयोजन

उल्हासनगर। उल्हासनगर के प्रसिद्ध योगाचार्य सतीश शीतलाप्रसाद शर्मा (आयुष मंत्रालय) द्वारा महाकाल की नगरी उज्जैन में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर तीन दिवसीय शिव-शक्ति साधना विशेष ध्यान शिविर का भव्य आयोजन किया गया। इस शिविर में मुंबई, पुणे, सूरत और अहमदाबाद जैसे शहरों से आए साधकों ने माता हरसिद्धि, गढ़कालिका और बाबा महाकाल के दर्शन के साथ-साथ गहन आध्यात्मिक साधना का अनुभव प्राप्त किया। सप्तध्यान फाउंडेशन के संस्थापक और ₹सतीश शर्मा योगा हेल्थ₹ यूट्यूब चैनल के माध्यम से 50 देशों में योग का प्रचार कर रहे सतीश शर्मा ने इस आयोजन के जरिए समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया। शिविर के दौरान रामनवमी पर मौन तीर्थ आश्रम में महामंडलेश्वर डॉ. सुमनानंद गिरि जी महाराज के सानिध्य में विशेष पूजन हुआ, जिसके बाद साधकों ने क्षिप्रा नदी के तट पर राम ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति और नई आध्यात्मिक दिशा प्राप्त की।

प्रतिमा स्थानांतरण को लेकर राज असरोंडकर की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल

उल्हासनगर। उल्हासनगर के शांति नगर श्मशान भूमि में बिना अनुमति स्थापित डॉ. बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग को लेकर ₹कायद्याने वागार संस्था के अध्यक्ष राज असरोंडकर ने अपने घर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आंदोलनकर्ता का आरोप है कि मनपा आयुक्त मनीषा अव्हाले और प्रशासन राजनीतिक दबाव के कारण इस अनाधिकृत निर्माण पर कार्रवाई करने के बजाय इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। इस संवेदनशील मामले में शिवसेना (शिंदे समूह) ने भी अपना रुख स्पष्ट करते हुए आंदोलन का समर्थन किया है; सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे ने मनपा आयुक्त को पत्र लिखकर प्रतिमा को सम्मानपूर्वक किसी उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की है। राज असरोंडकर का कहना है कि श्मशान भूमि में प्रतिमा स्थापित करना महापुरुषों का अनादर है और प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ उनका यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होती।

पश्चिम रेलवे ने रचे नए कीर्तिमान

हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्ज

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

पश्चिम रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में एक बार फिर सर्वांगीण उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए माल ढुलाई, अवसंरचना, सुरक्षा, यात्री सेवाओं और राजस्व सृजन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। यह उपलब्धि जोन के सभी विभागों के समन्वित प्रयासों और कुशल संचालन का परिणाम है।

यात्री सेवाओं में विस्तार और सुधार

रेलवे ने 17 नई ट्रेनों की शुरुआत की और 116 ट्रेनों की गति बढ़ाई। 11,000 से अधिक हॉलिडे स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। मुंबई उपनगरीय सेवाओं में भी सुधार करते हुए कुल सेवाएं 1414 की गईं और 411 महिला डिब्बों में इमरजेंसी टॉक-बैक सिस्टम लगाया गया ।यात्री राजस्व 8,490 करोड़ और माल राजस्व 14,257 करोड़ रहा। टिकट जांच से 209 करोड़ की रिकॉर्ड आय हुई, जबकि गैर-भाड़ा राजस्व 133 .26 करोड़ तक पहुंचा। स्क्रैप बिक्री से 654 करोड़ की आय अर्जित कर लक्ष्य से 40% अधिक प्रदर्शन किया गया। पश्चिम रेलवे ने 'SUGAM RAIL' ऐप लॉन्च किया, जो परिसंपत्तियों की रियल-टाइम निगरानी और मेंटेनेंस ट्रैकिंग की सुविधा देता है। इसके अलावा मुंबई सेंट्रल, वडोदरा और अहमदाबाद स्टेशनों पर डिजिटल लाउंज और को-वर्किंग स्पेस भी शुरू किए गए।

अवसंरचना विकास में बड़ी उपलब्धियां

इस अवधि में 252 किमी नई लाइन, गेज परिवर्तन और दोहरीकरण कार्य पूरा किया गया, जबकि 206 रूट किलोमीटर विद्युतीकरण के साथ पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क 100% विद्युतीकृत हो गया। साथ ही 660 किमी पर 'कवच' सुरक्षा तकनीक स्थापित की गई और 162 रोड ओवरब्रिज/अंडरब्रिज का निर्माण कर रिकॉर्ड बनाया गया।

सुरक्षा और गति में सुधार

पश्चिम रेलवे ने 100 मानवयुक्त समपार फाटकों को समाप्त किया और 19 स्थायी गति प्रतिबंध हटाए। मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की समयपालनता लगभग 96% रही, जो भारतीय रेल में सर्वश्रेष्ठ है। दाहोद वर्कशॉप से देश का पहला 9000 हॉर्सपावर विद्युत इंजन भी तैयार किया गया। वर्ष 2025-26 में लगभग 106 मिलियन टन माल लोडिंग के साथ पश्चिम रेलवे ने लगातार चौथे वर्ष 100 मिलियन टन क्लब में अपनी जगह बनाई।

'यात्री ऐप' के साथ मध्य रेल की साझेदारी 2031 तक बढ़ी

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

मध्य रेल ने मुंबई उपनगरीय नेटवर्क के यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए 'यात्री ऐप' के साथ अपनी साझेदारी को और सुदृढ़ करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को सटीक और रीयल-टाइम ट्रेन जानकारी उपलब्ध कराना है। यह सहयोग अप्रैल 2021 में पांच वर्षों के लिए टेंडर के माध्यम से शुरू किया गया था। सफल क्रियान्वयन के बाद अब इस साझेदारी को बढ़ाकर मार्च 2031 तक विस्तारित कर दिया गया है। 'यात्री ऐप' के जरिए मध्य रेल को लाइसेंस शुल्क के रूप में हर वर्ष 22.05 लाख का राजस्व प्राप्त हो रहा है, जो इस सहयोग को आर्थिक रूप से भी लाभकारी बनाता है।

दुनिया के व्यस्ततम नेटवर्क में बेहतर सुविधा

मुंबई का उपनगरीय रेल नेटवर्क दुनिया के सबसे व्यस्त शहरी रेल तंत्रों में शामिल है। इस साझेदारी से लाखों यात्रियों को लाइव ट्रेन लोकेशन, देरी की जानकारी और प्लेटफॉर्म अपडेट जैसी सुविधाएं समय पर मिल रही हैं। 'यात्री ऐप' स्थानीय ट्रेनों में लगे जीपीएस उपकरणों से प्राप्त डेटा का उपयोग करता है। इसके माध्यम से यात्रियों को ट्रेनों की सटीक स्थिति की जानकारी मिलती है, जिससे उनकी यात्रा अधिक सुगम हो जाती है।

प्रतिदिन 25 लाख से अधिक यात्रियों को लाभ

इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रतिदिन 25 लाख से ज्यादा यात्रियों को सहायता मिल रही है। इससे यात्रियों को अपने सफर की बेहतर योजना बनाने और समय बचाने में मदद मिलती है। 'यात्री ऐप' के उपयोग से मुंबई की बस सेवाओं और मेट्रो जैसे अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों के साथ भी बेहतर तालमेल स्थापित हुआ है, जिससे शहर का समग्र परिवहन तंत्र मजबूत हुआ है।

ठाणे मनपा का रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, 878 करोड़ रुपये वसूले

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

ठाणे महानगरपालिका (मनपा) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन का नया रिकॉर्ड बनाते हुए 878.37 करोड़ रुपये वसूले हैं। यह निर्धारित 915 करोड़ रुपये के लक्ष्य का करीब 96 प्रतिशत है, जिसे मनपा की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में 810 करोड़ रुपये का टैक्स कलेक्शन हुआ था, जबकि इस साल 68.37 करोड़ रुपये अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

टैक्सपेयर्स को दिया श्रेय

मेयर शर्मिला पिंपलोलकर और मनपा आयुक्त सौरभ राव ने इस सफलता का श्रेय नागरिकों को देते हुए टैक्सपेयर्स का आभार व्यक्त किया है। मनपा ने टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए, जिनमें ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा शुरू करना और तत्काल रसीद उपलब्ध कराना शामिल है। ऑनलाइन के साथ-साथ कलेक्शन सेंटर्स पर भी चेक, डिमांड ड्राफ्ट, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए टैक्स जमा करने की सुविधा दी गई।

मोबाइल वैन और SMS से जागरूकता

जनवरी से मार्च 2026 के बीच छुट्टियों में भी कलेक्शन सेंटर खुले रखे गए। ऑटो रिक्शा और हाउसिंग सोसाइटियों में मोबाइल वैन के जरिए जागरूकता अभियान चलाया गया, वहीं SMS के माध्यम से लोगों को टैक्स भरने की याद दिलाई गई। समय पर टैक्स नहीं भरने वाले नागरिकों के खिलाफ मनपा ने सख्त कार्रवाई करते हुए प्रॉपर्टी सीज करने, वारंट जारी करने और सेवाएं रोकने जैसे कदम उठाए।

मध्य रेल ने स्क्रैप बिक्री से 459.52 करोड़ कमाए

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

वित्त वर्ष 2025-26 में मध्य रेल ने स्क्रैप की बिक्री के जरिए 459.52 करोड़ का राजस्व अर्जित कर अपनी "जीरो स्क्रैप स्टेटस" नीति को और मजबूत किया है। 31 मार्च 2026 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, मध्य रेल ने रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित 450 करोड़ के लक्ष्य को पार कर लिया है। यह उपलब्धि वित्त वर्ष 2023-24 के बाद सबसे अधिक है और पिछले दो वर्षों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी माना जा रहा है। इस राजस्व में विभिन्न प्रकार के स्क्रैप और अपशिष्ट सामग्री के व्यवस्थित निपटान का अहम योगदान रहा। इसमें 47,502 मीट्रिक टन रेल पथ स्क्रैप, 31,298 मीट्रिक टन लौह स्क्रैप, 3,616 मीट्रिक टन अलौह स्क्रैप, 2,65,625 स्लीपर तथा 50 इंजन, 78 कोच और 137 वैगनों का निपटान शामिल है। मध्य रेल के स्टोर्स विभाग ने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुर्ला कटिंग यार्ड, नासिक की ट्रैक्शन मशीन वर्कशॉप, परेल और मनमाड वर्कशॉप सहित विभिन्न स्थानों पर पड़े स्क्रैप की पहचान और निपटान के लिए विशेष अभियान चलाया गया।

भुसावल मंडल रहा सबसे आगे

स्क्रैप बिक्री में भुसावल मंडल ने 105 .39 करोड़ के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके बाद माटुंगा वर्कशॉप ने 68 .39 करोड़, नागपुर मंडल 64 .02 करोड़, मुंबई मंडल 55 .49 करोड़ और पुणे मंडल ने 50 करोड़ का योगदान दिया। मध्य रेल ने केवल स्क्रैप निपटान ही नहीं, बल्कि उपयोगी संसाधनों के पुन: उपयोग पर भी ध्यान दिया। एक रोटाटेक प्रिंटिंग मशीन, जो उपयोग में नहीं थी लेकिन कार्यशील थी, उसे स्क्रैप करने के बजाय 8 .75 करोड़ में नासिक प्रिंटिंग प्रेस को हस्तांतरित किया गया।

महाराष्ट्र मछली निर्यात में देश में दूसरे स्थान पर

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र ने मछली निर्यात के क्षेत्र में एक बार फिर अपनी ताकत साबित करते हुए देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में महाराष्ट्र से 7,343.40 करोड़ का मछली निर्यात हुआ। यह आंकड़ा वर्ष 2020-21 के 3,684 करोड़ की तुलना में लगभग दोगुना है, जो इस क्षेत्र की तेज़ी से बढ़ती क्षमता को दर्शाता है।

निर्यात वॉल्यूम में भी हुआ इजाफा

महाराष्ट्र से मछली निर्यात का वॉल्यूम बढ़कर 2 .27 लाख मीट्रिक टन सालाना हो गया है। यह वृद्धि राज्य के उत्पादन, प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन में सुधार का परिणाम मानी जा रही है। राज्य के कोंकण तट ने इस सफलता में अहम भूमिका निभाई है। विशेष रूप से झींगा और फ्रोजन मछली के निर्यात में इस क्षेत्र का बड़ा योगदान है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में महाराष्ट्र की पहचान मजबूत हुई है। कोंकण के प्रॉन्स की अमेरिका और चीन जैसे बड़े बाजारों में भारी मांग है। अपनी गुणवत्ता और स्वाद के कारण ये उत्पाद विदेशी ग्राहकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। भारत के कुल मछली निर्यात में अमेरिका सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है, जहाँ 2024-25 में 22,723 करोड़ का निर्यात हुआ। इसके बाद चीन, यूरोपियन यूनियन, दक्षिण-पूर्व एशिया और जापान का स्थान है।

भुसावल मंडल ने हासिल किया 1,736 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

मध्य रेलवे के भुसावल मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में 1,736 करोड़ का अब तक का सर्वाधिक कुल राजस्व अर्जित कर नया इतिहास रच दिया है। यह पिछले वित्तीय वर्ष 2024–25 के 1,628.49 करोड़ के मुकाबले 6.62% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है, जो मंडल की मजबूत वित्तीय स्थिति को रेखांकित करता है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में यात्री राजस्व 938.01 करोड़ रहा, जिसमें 9.01% की वृद्धि दर्ज की गई।

माल परिवहन में रिकॉर्ड प्रदर्शन

मंडल ने माल परिवहन के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ऑटोमोबाइल परिवहन से 51.49 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जो अब तक का सर्वोच्च है। मक्का परिवहन से 83 .95 करोड़ और खाद्यान्न परिवहन से 89 .46 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया गया।

टिकट जांच में रिकॉर्ड उपलब्धि

टिकट जांच अभियानों को सुदृढ़ बनाते हुए मंडल ने 81 .23 करोड़ का राजस्व अर्जित किया, जो 14 .31% की वृद्धि है। साथ ही 9 .63 लाख मामलों का निपटारा किया गया, जो पिछले रिकॉर्ड से 4 .66% अधिक है।

गैर-भाड़ा राजस्व में मजबूती

भुसावल मंडल ने गैर-भाड़ा आय के स्रोतों को भी प्रभावी ढंग से बढ़ाया है। पार्किंग अनुबंध से 5 .21 करोड़ (16 .04% वृद्धि), कैटरिंग सेवाओं से 11 .30 करोड़ और वाणिज्यिक विज्ञापन से 8 .00 करोड़ (5 .54% वृद्धि) का राजस्व प्राप्त हुआ।

एल्फिन्स्टन रोड आरओबी कार्य के लिए पावर ब्लॉक

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

मध्य रेल, मुंबई मंडल द्वारा परेल और करी रोड स्टेशनों के बीच स्थित एल्फिन्स्टन रोड रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के पैनलों को हटाने के लिए 2/3 अप्रैल और 3/4 अप्रैल 2026 की मध्यरात्रि को विशेष ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लिया जाएगा। 3 अप्रैल को रात 12:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक अप स्लो लाइन तथा अप एवं डाउन फास्ट लाइनों पर ब्लॉक रहेगा, जबकि 4 अप्रैल को इसी समयावधि में अप फास्ट लाइन पर ब्लॉक लिया जाएगा।

ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन और अतिरिक्त ठहराव

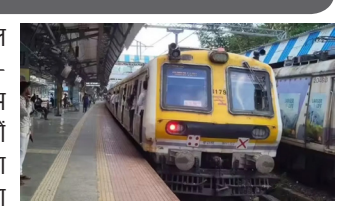

इस ब्लॉक के चलते 2/3 अप्रैल की रात 11020 भुवनेश्वर–सीएसएमटी कोणार्क एक्सप्रेस को माटुंगा और भायखला स्टेशनों के बीच डायवर्ट किया जाएगा तथा दादर स्टेशन पर इसे दोहरा ठहराव दिया जाएगा। वहीं 3/4 अप्रैल की रात कोणार्क एक्सप्रेस के अलावा 12810 हावड़ा–सीएसएमटी मेल और 12134 मंगलुरु–सीएसएमटी एक्सप्रेस को भी इसी मार्ग पर डायवर्ट किया जाएगा और दादर स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव दिया जाएगा।

पड़वा पर महारेरा का 'उपहार'

1060 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी

486 नए प्रोजेक्ट्स को मिला रजिस्ट्रेशन नंबर

दीपक पवार | मुंबई

हिंदू नववर्ष और गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर महाराष्ट्र के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। घर खरीदारों और बिल्डरों के लिए इस 'साढ़े तीन मुहूर्त' के महत्व को देखते हुए, महारेरा ने रिकॉर्ड तोड़ तेजी दिखाते हुए 1060 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी है। रियल एस्टेट में गुड़ी पड़वा को घर की बुकिंग के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। डेवलपर्स की भारी मांग और जनता के उत्साह को देखते हुए महारेरा के रजिस्ट्रेशन विभाग ने 24 घंटे काम किया। यहां तक कि छुट्टियों में भी स्टाफ ने पसीना बहाया ताकि पड़वा से ठीक एक दिन पहले 211 केस निपटाए जा सकें।

पुणे और मुंबई का दबदबा

प्रोजेक्ट्स की संख्या के मामले में पुणे (286 प्रोजेक्ट्स) सबसे आगे निकल गया है। इसके बाद मुंबई सबअर्बन (196), ठाणे (185) और रायगढ़ (110) का नंबर आता है। कोंकण और मुंबई क्षेत्र से कुल 607 प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिली है, जो दर्शाता है कि यहां रियल एस्टेट की मांग कितनी तेज है। महारेरा ने साफ किया है कि काम जल्दी करने का मतलब यह नहीं कि नियमों में ढील दी गई है। हर प्रोजेक्ट की कानूनी, टेक्निकल और फाइनेंशियल जांच कड़ी शर्तों के आधार पर की गई है। महारेरा का मकसद है कि खरीदारों का पैसा सुरक्षित रहे और उन्हें तय समय पर घर मिले। केवल बड़े शहर ही नहीं, बल्कि राज्य के अन्य हिस्सों में भी नए घर बनेंगे। विदर्भ में 50, खानदेश में 63 और मराठवाड़ा में 14 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। दादरा और नगर हवेली में भी 5 प्रोजेक्ट्स को नंबर आवंटित किए गए हैं।

नए रजिस्ट्रेशन और एक्सटेंशन की झड़ी

- कुल 1060 प्रोजेक्ट्स की फाइलें मंजूर की गई हैं।
- 486 नए प्रोजेक्ट्स: इन्हें पहली बार महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है।
- 426 प्रोजेक्ट्स को एक्सटेंशन: डेवलपर्स की विनती पर काम पूरा करने की समय सीमा बढ़ाई गई है।
- 148 प्रोजेक्ट्स में बदलाव: पुराने प्रोजेक्ट्स के नक्शों या प्लान में जरूरी सुधारों को मंजूरी दी गई है।

12 राशिफल में देखें अपना दिन

प्रियंका जैन
97699 94439

मेष धर्म-कर्म में रुचि रहेगी। कोर्ट व कचहरी के काम मनोनुकूल रहेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। कुबुद्धि हावी रहेगी। चिंता तथा तनाव रहेंगे। मित्रों से संबंध सुधरेंगे। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। विरोधी सक्रिय रहेंगे। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रह सकता है।

वृष वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। पुराना रोग परेशानी का कारण रह सकता है। दूसरों के कार्य में दखल न दें। बड़ों की सलाह मानें। लाभ होगा। अपेक्षित कार्यों में विलंब होगा। मानसिक बेचैनी रहेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। आय में निश्चितता रहेगी। धैर्य रखें।

मिथुन प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। बेवजह कहासुनी हो सकती है। कानूनी अड़चन दूर होगी। व्यापार में वृद्धि होगी। नौकरी में सहकर्मियों का साथ मिलेगा। निवेश शुभ रहेगा। प्रसन्नता रहेगी।

कर्क किसी अपने के व्यवहार से स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है। शारीरिक कष्ट संभव है। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। शत्रु पस्त होंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें। स्थायी संपत्ति के कार्य बड़ा लाभ दे सकते हैं। आर्थिक उन्नति के प्रयास सफल होंगे।

सिंह घर के सदस्यों के स्वास्थ्य व अध्ययन संबंधी चिंता रहेगी। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा। यात्रा मनोरंजक रहेगी। दुष्टजनों से दूरी बनाए रखें। निवेश शुभ रहेगा। व्यापार में वृद्धि होगी।

कन्या शत्रु हानि पहुंचा सकते हैं। दु:खद समाचार मिल सकता है। व्यर्थ भागदौड़ रहेगी। लाभ के अवसर हाथ से निकलेंगे। बेवजह कहासुनी हो सकती है। पुराना रोग उभर सकता है। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। व्यापार ठीक चलेगा। आय में निश्चितता रहेगी।

तुला शत्रु पस्त होंगे। सुख के साधन जुटेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पराक्रम बढ़ेगा। लंब समय से रुके कार्य सहज रूप से पूर्ण होंगे। कार्य की प्रशंसा होगी। शेयर मार्केट में सफलता मिलेगी। व्यापार-व्यवसाय में वृद्धि होगी।

वृश्चिक घर में अतिथियों का आगमन होगा। व्यय होगा। दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यापार-व्यवसाय ठीक चलेगा। आय बनी रहेगी। अज्ञात भय रहेगा। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी।

धनु आंखों का ख्याल रखें। अज्ञात भय सताएगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। कानूनी अड़चन आ सकती है। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। लॉटरी व सट्टे से दूर रहें। बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे।

मकर स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। किसी अपरिचित पर अतिविश्वास न करें। विवाद से क्लेश होगा। दूसरों के उकसाने में न आएं। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। चिंता तथा तनाव रहेंगे। व्यवसाय की गति धीमी रहेगी। आय में निश्चितता रहेगी।

कुंभ शारीरिक कष्ट संभव है तथा तनाव रहेंगे। सुख के साधन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। लंबे समय से रुके कार्यों में गति आएगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

मीन चोट व रोग से परेशानी संभव है। आराम तथा मनोरंजन के साधन उपलब्ध होंगे। यश बढ़ेगा। व्यापार वृद्धि होगी। नई योजना बनेगी जिसका तत्काल लाभ नहीं मिलेगा। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। विरोधी सक्रिय रहेंगे। नौकरी में उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। प्रमाद न करें।

शेषनाग कालसर्प दोष: जीवन के संघर्ष, कर्म और समाधान की गहन व्याख्या

प्रियंका जैन
97699 94439

वैदिक ज्योतिष में "कालसर्प दोष" को एक विशेष और प्रभावशाली योग माना जाता है, जो व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा दोनों को प्रभावित करता है। जब जन्म कुंडली में राहु और केतु ऐसे स्थानों पर स्थित होते हैं कि सभी ग्रह उनके बीच आ जाते हैं, तब पूर्ण कालसर्प दोष का निर्माण होता है। शेषनाग कालसर्प दोष उसी का एक विशेष रूप है, जिसमें राहु बारहवें भाव में और केतु छठे भाव में स्थित होते हैं। यह स्थिति जीवन में कई प्रकार की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकती है, लेकिन इसके साथ ही यह एक गहरा आध्यात्मिक संकेत भी देती है कि व्यक्ति अपने कर्मों और आत्मबल से ऊपर उठ सकता है।

शेषनाग कालसर्प दोष वाले व्यक्ति का मन अक्सर अस्थिर रहता है। उसे बिना कारण चिंता, भय और तनाव का अनुभव होता है। जीवन में एक अजीब-सी बेचैनी बनी रहती है, जैसे कुछ अधूरा है या कुछ छूट रहा है। ऐसे व्यक्ति अक्सर छोटी-छोटी बातों पर अधिक प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे उनका स्वभाव चिड़चिड़ा और क्रोधपूर्ण हो सकता है। यह क्रोध केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि भीतर भी एक निरंतर द्वंद्व चलता रहता है, जो व्यक्ति को मानसिक रूप से थका देता है। अनिद्रा, नकारात्मक विचार और आत्मविश्वास की कमी भी इसके सामान्य लक्षण हैं।

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह दोष विशेष रूप से पेट और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। व्यक्ति को गैस, एसिडिटी, पाइल्स, फिस्टुला और फिशर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कई बार अचानक दुर्घटनाएं या चोट लगने की संभावना भी बनी रहती है, जिससे जीवन में असुरक्षा की भावना बढ़ती है। यह दोष शरीर की ऊर्जा को असंतुलित करता है, जिससे व्यक्ति हमेशा थका हुआ या कमजोर महसूस करता है, भले ही बाहरी रूप से सब कुछ सामान्य दिखे।

आर्थिक जीवन में भी यह दोष बाधाएं उत्पन्न करता है। व्यक्ति मेहनती होता है, लेकिन उसे अपने प्रयासों के अनुरूप फल नहीं मिल पाता। बार-बार धन हानि, कर्ज में फंसना या अचानक खर्चों का बढ़ जाना उसकी आर्थिक स्थिति को अस्थिर बना देता है। इसके साथ ही छुपे हुए शत्रु, धोखाधड़ी और विश्वासघात जैसी परिस्थितियाँ भी सामने आ सकती हैं। कई बार व्यक्ति अनावश्यक कानूनी मामलों में उलझ जाता है, जिससे समय और धन दोनों का नुकसान होता है।

वैवाहिक जीवन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। विवाह में देरी होना, रिश्तों का बार-बार टूटना या विवाह के बाद भी मनमुटाव और तनाव बना रहना आम बात होती है। पति-पत्नी के बीच समझ की कमी, संदेह और विवाद इस दोष के कारण बढ़ सकते हैं। कुछ मामलों में यह स्थिति तलाक तक भी पहुंच सकती है, यदि समय रहते समझदारी और धैर्य से काम न लिया जाए। यह दोष व्यक्ति के संबंधों में स्थिरता को चुनौती देता है, लेकिन साथ ही यह सिखाता भी है कि सच्चे रिश्ते केवल धैर्य, विश्वास और त्याग से ही टिकते हैं।

जीवन में बार-बार असफलता का अनुभव भी इस दोष की एक प्रमुख पहचान है। व्यक्ति को लगता है कि वह हर बार लक्ष्य के करीब पहुंचकर पीछे रह जाता है। यह स्थिति उसे निराश कर सकती है, लेकिन यही वह बिंदु है जहां से आत्मविकास की शुरुआत होती है। कई बार ऐसे व्यक्ति को विदेश जाने की तीव्र इच्छा होती है, लेकिन उसमें भी बाधाएं आती हैं। सांपों का डर या उनसे जुड़े सपने आना भी इस दोष का एक सूक्ष्म संकेत माना जाता है।

निगम को 250 E-CNG गाड़ियों की सौगात

- योगी ने वाहनों को दिखाई हरी झंडी, कूड़ा प्रबंधन को मिली रफ्तार
- नौ वर्षों के दौरान सूबे में स्वच्छता को लेकर हुए व्यापक सुधार :योगी

एजेंसी । लखनऊ

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ नगर निगम के लिए 250 इलेक्ट्रिक और सीएनजी आधारित वाहनों को हरी झंडी दिखाई। ये वाहन डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में प्रदेश में स्वच्छता को लेकर व्यापक सुधार हुआ है।

'नेट जीरो' उत्सर्जन का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने बताया कि लखनऊ आज स्वच्छता के मानकों पर देश के शीर्ष तीन शहरों में शामिल हो चुका है और अब सरकार 'नेट जीरो' उत्सर्जन के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, हरित ऊर्जा का उपयोग और प्रदूषण नियंत्रण प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के बाद शहरी बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर सुधार किए गए हैं।

18 नगर निगम कंट्रोल सेंटर से जुड़े

सरकार ने शहरी सुरक्षा और प्रबंधन के लिए 17 नगर निगमों और नोएडा-ग्रेटर नोएडा सहित कुल 18 शहरों को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा है। साथ ही इन शहरों को 'सोलर सिटी' के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कार्य जारी है। अयोध्या में सौर ऊर्जा आधारित प्रकाश व्यवस्था लागू की जा चुकी है, जबकि लखनऊ में भी रूफटॉप सोलर पैनलों का विस्तार किया जा रहा है।

बढ़ रहा इलेक्ट्रिक बसों का दायरा

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को भी आधुनिक बनाया गया है। लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा जैसे शहरों में मेट्रो सेवाएं संचालित हैं, जबकि इलेक्ट्रिक बसों का दायरा तेजी से बढ़ाया जा रहा है। इससे शहर के भीतर लोगों को आवागमन सहूलियत होगी और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाए जा रहे प्रयासों का लाभ मिलेगा। डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण को स्वच्छता अभियान का अहम हिस्सा बताते हुए उन्होंने कहा कि नए शामिल किए गए वाहन वार्ड स्तर पर कचरा प्रबंधन को और सशक्त करेंगे। इससे शहर को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा, महापौर सुषमा खर्कवाल सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।

13000 आउटसोर्स कर्मियों को नहीं मिलेगी पक्की नौकरी

- स्थायी अनुबंध की मांग खारिज, अलग नीति नहीं बनाएगी सुक्खू सरकार

एजेंसी । शिमला

हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अलग से नौकरी सुरक्षा या स्थायी अनुबंध नीति की मांग को राज्य सरकार ने फिलहाल खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान लिखित जवाब में स्पष्ट किया कि सरकार आउटसोर्स कर्मियों के लिए कोई नई नीति लाने पर विचार नहीं कर रही है। भाजपा विधायक प्रकाश राणा और डॉ. जनक राज के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स आधार पर कार्यरत कर्मचारी सरकारी नियमित कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए उनके लिए अलग से सेवा सुरक्षा या दीर्घकालिक संविदा व्यवस्था बनाना प्रस्तावित नहीं है।

वेतन-शर्तों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न विभागों में इस समय करीब 13 हजार कर्मचारी आउटसोर्स माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमित पदों को आउटसोर्स के जरिए नहीं भरा जाता, बल्कि केवल कुछ विशिष्ट सेवाओं को हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के तहत निविदा प्रक्रिया के माध्यम से बाहरी एजेंसियों को सौंपा जाता है। वेतन और सेवा शर्तों के संबंध में सरकार ने बताया कि पहले ही 1 जुलाई 2017 और 18 जनवरी 2021 को दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

विशिष्ट सेवाओं के लिए आउटसोर्सिंग

विधायकों द्वारा पिछले दो वर्षों में वेतन भुगतान में देरी के मामलों को लेकर पूछे गए प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 जनवरी 2026 तक सरकार के संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है, जिसमें निर्धारित समयसीमा के बाद भुगतान हुआ हो। सरकार के इस रुख से प्रदेश के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच असंतोष की संभावना जताई जा रही है, जो लंबे समय से स्थायित्व और सेवा सुरक्षा की मांग उठा रहे हैं। इनके तहत सेवा प्रदाता एजेंसियों को कर्मचारियों का वेतन हर माह की 7 तारीख तक अनिवार्य रूप से जारी करना होता है, ताकि भुगतान में देरी न हो। संयुक्त आउटसोर्स कर्मचारी संघ के संयोजक अश्विनी शर्मा ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को न तो उचित वेतन मिल रहा है न नौकरी में सुरक्षा है।

बुजुर्ग दंपति की गला रेतकर हत्या, हार गायब

एजेंसी । जांजगीर-चांपा

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र स्थित खपरी गांव में हुए निर्मम दोहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। अज्ञात हमलावरों ने घर में सो रहे बुजुर्ग दंपति की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। घटना के बाद महिला के गले से सोने का हार गायब मिलने से लूट के इरादे की आशंका जताई जा रही है। मृतकों की पहचान 65 वर्षीय संतराम साहू और उनकी 62 वर्षीय पत्नी श्याम बाई साहू के रूप में हुई है। दोनों घर में अकेले रहते थे, जबकि उनके बेटे अलग स्थानों पर निवास करते हैं। घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है। घटना का खुलासा बुधवार सुबह उस समय हुआ जब उनका बेटा हरिशंकर साहू खेत में दवाई छिड़काव के लिए घर पहुंचा। घर का दरवाजा खुला देख उसे संदेह हुआ। अंदर प्रवेश करने पर उसने पिता का शव जमीन पर और मां का शव खाट पर खून से लथपथ पाया।

पहाड़पानी में खिला आत्मनिर्भरता का फूल

एजेंसी । नैनीताल

उत्तराखंड के नैनीताल जिले के धारी विकासखंड स्थित पहाड़पानी गांव के कमलेश महतोलिया ने यह साबित कर दिखाया है कि यदि संकल्प और सही मार्गदर्शन हो, तो पहाड़ों की जमीन भी सुनहरी संभावनाओं से भर सकती है। इंजीनियरिंग करने के बाद गुजरात में नौकरी कर चुके कमलेश ने गांव लौटकर आधुनिक खेती को अपनाया और आज एक सफल उद्यमी किसान के रूप में पहचान बना ली है। कमलेश ने उद्यान विभाग की सहायता से करीब 14 लाख रुपये का ऋण प्राप्त कर बंजर पड़ी जमीन को उपजाऊ बनाया और फूलों की उन्नत खेती शुरू की।

14 लाख के ऋण से शुरू किया सफर

छोटे स्तर पर 10 नाली भूमि से शुरू हुआ उनका प्रयास आज 40 नाली तक फैल चुका है, जहां लिलियम सहित विभिन्न प्रजातियों के फूलों की खेती की जा रही है। इसके साथ ही 30 नाली क्षेत्र में सेब, कीवी और स्ट्रॉबेरी जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों का उत्पादन भी किया जा रहा है।

31 मई से पहले होंगे पंचायत चुनाव

- हिमाचल में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू, रोस्टर में सीमित बदलाव की छूट

एजेंसी । शिमला

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 31 मई से पहले कराने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा कि सरकार निर्धारित समयसीमा के भीतर चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी संभावित कानूनी बाधा की स्थिति में समय-सीमा प्रभावित हो सकती है।

आरक्षण प्रभावी लेकिन पर्याप्त आबादी नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2010 में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए जो आरक्षण तय किया गया था, वह 1990-95 के सर्वेक्षण और उस समय की जनगणना के आधार पर निर्धारित था। वर्तमान में कई पंचायतों में ऐसी स्थिति है।

रोस्टर में संशोधन कर सकेंगे उपायुक्त

मुख्यमंत्री ने बताया कि पंचायत चुनाव वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ही आयोजित किए जाएंगे। साथ ही, जहां किसी विशेष वर्ग की पर्याप्त जनसंख्या नहीं होगी, वहां उपायुक्त रोस्टर में आवश्यक संशोधन कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि यह निर्णय प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक व्यावहारिक और संतुलित बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है, ताकि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व का उचित अवसर मिल सके।

रामावतार जग्गी हत्याकांड: CBI से फाइल तलब

- हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई की उलटी गिनती शुरू

एजेंसी । बिलासपुर

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में न्यायिक प्रक्रिया अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की विशेष डिवीजन बेंच ने मामले में अंतिम सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख तय करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को तत्काल केस से जुड़े सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

बचाव पक्ष को कोर्ट ने दिए 24 घंटे

अदालत ने साथ ही बचाव पक्ष को 24 घंटे के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा है, ताकि निर्धारित तिथि पर अंतिम सुनवाई में किसी प्रकार की देरी न हो। गौरतलब है कि यह मामला उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद पुनः उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए खोला गया है।

आज के फैसले पर टिकीं निगाहें

इससे पहले, करीब दो वर्ष पूर्व उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने दोषियों की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा था। हालांकि, बाद में उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई की अपील स्वीकार करते हुए मामले को पुनः उच्च न्यायालय को भेज दिया, ताकि साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर विस्तृत पुनर्विचार किया जा सके। अब गुरुवार को प्रस्तावित अंतिम सुनवाई को इस मामले में निर्णायक माना जा रहा है।

चार साल सेवा करने वाले कर्मी होंगे नियमित

- हिमाचल सरकार ने डेली वेज कर्मियों को दी राहत
- एक वर्ष 240 दिन का कार्य करना अनिवार्य पात्रता

एजेंसी । शिमला

हिमाचल प्रदेश सरकार ने डेली वेज और कंटीजेंट पेड कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर अहम निर्णय लिया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक लगातार चार वर्ष की सेवा।

रिक्त पदों के सापेक्ष होगा नियमितीकरण

नियमितीकरण केवल उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध ही किया जाएगा और इसके लिए नए पद सृजित नहीं किए जाएंगे। नियमित होने के बाद संबंधित कर्मचारी का डेली वेज या कंटीजेंट पद समाप्त माना जाएगा। पूरी प्रक्रिया विभागों को आवंटित बजट के भीतर ही पूरी की जाएगी और अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं डाला जाएगा। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी आवश्यक सरकार ने साफ किया है कि चार वर्ष की सेवा पूरी करना केवल पात्रता की शर्त है, जबकि नियमितीकरण आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा और इसे पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा। साथ ही, कर्मचारियों के पास नियुक्ति के समय निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना आवश्यक होगा, हालांकि विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी छूट दे सकता है।

चंदा एकत्र कर चुकाया पांच लाख का बिल

एजेंसी । सुपौल

बिहार के सुपौल जिले में रास्ते को लेकर शुरू हुआ विवाद एक परिवार के लिए गहरी त्रासदी में बदल गया। जदिया थाना क्षेत्र के मानगंज पश्चिम पंचायत में हुए हिंसक झगड़े में गंभीर रूप से घायल मजदूर मो. इजराइल की नेपाल के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का शव अस्पताल प्रशासन ने बिल भुगतान के बिना देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते शव दो दिनों तक अस्पताल में ही रखा रहा।

बिहार में खनन से रिकॉर्ड 3592 करोड़ की आमदनी

- डिजिटल निगरानी से पारदर्शिता में इजाफा

एजेंसी । पटना

बिहार सरकार के खनन एवं भूतत्व विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3,592 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। उपमुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री विजय सिन्हा ने बुधवार को प्रेस वार्ता में बताया कि यह में लागू की गई पारदर्शी नीतियों और सख्त निगरानी का परिणाम है। राज्य के 21 जिलों ने निर्धारित लक्ष्य का 100 प्रतिशत हासिल कर इस प्रदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

473 बालू घाट सक्रिय, 78 घाट सरेंडर

उन्होंने कहा कि पहले खनन क्षेत्र पर बाहुबलियों का प्रभाव रहा, लेकिन अब व्यवस्था पूरी तरह राजस्व-केंद्रित और नियंत्रणाधीन हो चुकी है। वर्तमान में राज्य में 473 बालू घाट सक्रिय हैं, जबकि 78 घाट संचालकों द्वारा छोड़ दिए गए। इन घाटों के समर्पण से लगभग 600 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ। मंत्री ने स्पष्ट किया शामिल नहीं किया जाएगा।

उल्लंघन पर 25 गुना तक जुर्माना

सरकार ने खनिज परिवहन को नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। अब दूसरे राज्यों से खनिज लेकर आने वाले वाहनों के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य होगा। नियमों के उल्लंघन पर 25 गुना तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पत्थर खनन को व्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकार ने 30 स्थानों की पहचान की है। इन क्षेत्रों के लिए जल्द ही नई नीति और संचालन प्रक्रिया की घोषणा की जाएगी।

व्यापार जगत

एक दिन में 9.82 लाख करोड़ का मुनाफा

- बाजार में लौटी तेजी, सेंसेक्स-निफ्टी मजबूत बंद

एजेंसी । नई दिल्ली

वैश्विक संकेतों में सुधार और पश्चिम एशिया संकट के जल्द सुलझने की उम्मीदों के बीच भारतीय शेयर बाजार ने दमदार वापसी दर्ज की। पिछले दो सत्रों की गिरावट के बाद बुधवार को बाजार में जोरदार खरीदारी देखने को मिली, हालांकि दिन के दूसरे हिस्से में मुनाफावसूली के कारण उतार-चढ़ाव भी रहा। इसके बावजूद बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों सूचकांक डेढ़ प्रतिशत से अधिक की मजबूती के साथ बंद हुए।

फार्मा को छोड़ सभी सेक्टर में खरीदी

सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो फार्मा सेक्टर को छोड़कर लगभग सभी क्षेत्रों में खरीदारी हावी रही। डिफेंस सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही और यह इंडेक्स 5 प्रतिशत से अधिक चढ़ा। इसके अलावा मीडिया, पीएसयू बैंक और कैपिटल गुड्स सेक्टर में भी 3 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई। आईटी, ऑटो, एफएमसीजी, मेटल और ऑयल एंड गैस सेक्टर भी हरे निशान में बंद हुए। दिन की शुरुआत में बाजार ने 2 प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ तेज रफ्तार पकड़ी।

हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.23% की गिरावट

हालांकि, फार्मास्यूटिकल शेयरों में बिकवाली के चलते बीएसई हेल्थकेयर इंडेक्स 0.23 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ। व्यापक बाजार में भी मजबूती बनी रही, जहां मिडकैप इंडेक्स 2.20 प्रतिशत और स्मॉलकैप इंडेक्स 3.40 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुए। आज के कारोबार में कुल मिलाकर बढ़त वाले शेयरों का दबदबा रहा। बीएसई में 4,437 शेयरों में ट्रेडिंग हुई, जिनमें से 3,828 शेयर बढ़त में बंद हुए। वहीं एनएसई में भी अधिकांश शेयर हरे निशान में रहे, जो बाजार में सकारात्मक रुझान को दर्शाता है।

ट्रेंट, इंटर ग्लोब टॉप गेनर्स की सूची में

दिग्गज शेयरों में ट्रेंट लिमिटेड, इंटरग्लोब एविएशन, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेज और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमुख गेनर्स रहे। वहीं डॉ रेड्डीज लेबोरेट्रीज, एचडीएफसी लाइफ, सिप्ला, सन फार्मास्यूटिकल्स और एनटीपीसी में गिरावट दर्ज की गई विश्लेषकों के अनुसार, बाजार में यह तेजी निवेशकों के भरोसे की वापसी और वैश्विक परिस्थितियों में संभावित सुधार के संकेत देती है। बाजार की इस मजबूती का सीधा लाभ निवेशकों को मिला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल 422.23 लाख करोड़ रुपये हो गया।

मार्च में GST कलेक्शन दो लाख करोड़ के पार

- कलेक्शन में मजबूती बरकरार, सालाना आधार पर 8.8% की वृद्धि

एजेंसी । नई दिल्ली

देश में वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह ने मार्च महीने में एक बार फिर मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2026 में सकल जीएसटी राजस्व 8.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2,00,064 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष मार्च के 1,83,845 करोड़ रुपये के मुकाबले उल्लेखनीय बढ़ोतरी है। जीएसटी महानिदेशालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, इस वृद्धि के पीछे घरेलू कारोबार और आयात से मिलने वाले कर संग्रह में तेजी प्रमुख कारण रही है।

रिफंड में 13.8 प्रतिशत का इजाफा

वहीं, करदाताओं को जारी किए जाने वाले 'रिफंड' में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मार्च में कुल रिफंड राशि 13.8 प्रतिशत बढ़कर 22,074 करोड़ रुपये हो गई। रिफंड समायोजन के बाद शुद्ध जीएसटी संग्रह लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपये रहा, जो सालाना आधार पर 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वहीं, रिफंड समायोजन के बाद शुद्ध राजस्व 7.1 प्रतिशत बढ़कर 19.34 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल से मार्च) के आंकड़ों पर नजर डालें तो सकल जीएसटी संग्रह 8.3 प्रतिशत बढ़कर 22.27 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। वहीं, रिफंड समायोजन के बाद शुद्ध राजस्व 7.1 प्रतिशत बढ़कर 19.34 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। विशेषज्ञों के अनुसार, जीएसटी संग्रह में यह लगातार वृद्धि देश में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार, आयात में तेजी और बेहतर कर अनुपालन को दर्शाती है, जो राजस्व प्रणाली की मजबूती का संकेत है। मार्च के दौरान घरेलू स्रोतों से राजस्व 5.9 प्रतिशत बढ़कर 1.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जबकि आयात से प्राप्त कर 17.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 53,861 करोड़ रुपये रहा।

कमर्शियल LPG महंगा: 195.50 रुपये बढ़ी कीमत

- नई कीमतें एक अप्रैल से प्रभावी, 19 किलो का सिलेंडर 2078.5 रुपये का

एजेंसी । नई दिल्ली

वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में 195.50 रुपये की वृद्धि की है। संशोधित दरें बुधवार से प्रभावी हो गई हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट के अनुसार, इस बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2,078.50 रुपये हो गई है।

घरेलू सिलेंडर के दाम यथावत

हालांकि, घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत बरकरार है। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है और दिल्ली में इसकी कीमत 913 रुपये पर स्थिर है। इससे पहले 7 मार्च को घरेलू सिलेंडर के दाम में 60 रुपये की वृद्धि की गई थी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष मार्च में पेट्रोल और डीजल के दाम में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती के बाद से ईंधन की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं।

बीते मार्च में दो रुपये बढ़े थे दाम

फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। तेल कंपनियां हर महीने अंतरराष्ट्रीय बाजार भाव और विनिमय दर के आधार पर एलपीजी व एटीएफ की कीमतों की समीक्षा करती हैं। इससे पहले 1 मार्च को भी सिलेंडर के दाम में 114.50 रुपये का इजाफा किया गया था। पिछले साल भी कुल 60000 करोड़ रुपये के नुकसान में से आधा बोझ सरकार और आधा ऑयल कंपनियों ने उठाया था। ताकि, अंतरराष्ट्रीय कीमतों का असर सीधे जनता पर न पड़े।

टिप्को इंजीनियरिंग की फीकी लिस्टिंग, निवेशकों में निराशा

एजेंसी । नई दिल्ली

इंडस्ट्रियल मशीनरी कंपोनेंट बनाने वाली टिप्को इंजीनियरिंग इंडिया ने शेयर बाजार में निराशाजनक शुरुआत की। कंपनी के शेयर 89 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर महज 0.28 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 89.25 रुपये पर सूचीबद्ध हुए, लेकिन शुरुआती कारोबार के बाद बिकवाली हावी हो गई। लिस्टिंग के तुरंत बाद शेयर फिसलकर 84.81 रुपये तक पहुंच गया। बीच सत्र में थोड़ी खरीदारी से यह 90 रुपये तक उछला, लेकिन यह तेजी टिक नहीं सकी और अंत में शेयर 84.79 रुपये के लोअर सर्किट पर बंद हुआ।

दोगुनी हुई जेट फ्यूल की कीमत

- एक दिन में 96638 रुपये प्रति किलोलीटर का इजाफा

एजेंसी । नई दिल्ली

नए वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ ही एविएशन सेक्टर पर लागत का दबाव बढ़ गया है। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) यानी जेट फ्यूल की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि कर दी है, जिसके बाद पहली बार इसकी दर 2 लाख रुपये प्रति किलोलीटर के स्तर को पार कर गई है। इससे पहले 1 मार्च को भी कीमतों में 5,244.75 रुपये प्रति किलोलीटर (5.70 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई थी।

एक मार्च को बढ़े थे 5.7% दाम

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एटीएफ की कीमत 1,10,703.08 रुपये प्रति किलोलीटर से बढ़ाकर 2,07,341.22 रुपये प्रति किलोलीटर कर दी गई है, जो लगभग 114.5 प्रतिशत की तेज उछाल को दर्शाती है। यह लगातार दूसरा महीना है जब जेट फ्यूल महंगा हुआ है।

किराए में वृद्धि से इनकार नहीं

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी तेल कंपनियां हर महीने अंतरराष्ट्रीय बाजार और विनिमय दरों के आधार पर एटीएफ की कीमतों की समीक्षा करती हैं विशेषज्ञों के मुताबिक, जेट फ्यूल की कीमतों में यह तेज बढ़ोतरी एयरलाइंस की परिचालन लागत (ऑपरेटिंग कॉस्ट) को सीधे प्रभावित करेगी। ऐसे में आने वाले समय में हवाई किरायों में वृद्धि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम एशिया में जारी तनाव इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है।

2022 में भी ऐसे ही बढ़े थे दाम

उल्लेखनीय है कि इससे पहले वर्ष 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भी जेट फ्यूल की कीमतों में तेज उछाल देखा गया था, जब यह करीब 1.10 लाख रुपये प्रति किलोलीटर तक पहुंच गई थी। हालांकि बाद में कीमतों में गिरावट आई थी। मौजूदा परिदृश्य में कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी और आपूर्ति बाधाओं के कारण एविएशन सेक्टर के सामने नई चुनौतियां खड़ी होती दिख रही हैं, जिसका सीधा असर यात्रियों की जेब पर पड़ सकता है। जिसके बाद पहली बार इसकी दर 2 लाख रुपये प्रति किलोलीटर के स्तर को पार कर गई है।

हैदराबाद-कोलकाता को पहली जीत की तलाश

- दोनों टीमें आज ईडन गार्डस में होंगी आमने-सामने
- कोलकाता नाइट राइडर्स स्पिनरों के बूते अपने गढ़ में अभियान पटरी पर लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे

एजेंसी। कोलकाता

सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की टीमें गुरुवार को ईडन गार्डस में सत्र की पहली जीत के लिए एक-दूसरे से टकराएंगी। दोनों की बल्लेबाजी दमदार है। गेंदबाजों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। कोलकाता की टीम घरेलू मैदान पर स्पिनरों के बूते अपना अभियान पटरी पर लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी।यह मुकाबला तीन बार के चैंपियन कोलकाता के लिए घरेलू मैदान पर होने वाले महत्वपूर्ण दौर की शुरुआत भी है। उसे आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यहां सात दिन में तीन मैच और फिर 19 अप्रैल को एक और मैच खेलना है। विधानसभा चुनाव के कारण कोलकाता में लगभग एक महीने तक कोई मैच नहीं खेला जाएगा। इसके बाद चार मैच दूसरी टीमों के घरेलू मैदान पर खेलने हैं। उसका अपने घरेलू मैदान पर अगला मैच 16 मई को होगा। ऐसे में उसकी टीम इस चरण में लय हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

चक्रवर्ती-नारायण बढ़ा रहे चिंता

कुछ प्रमुख गेंदबाजों के चोटिल होने के कारण बाहर होने से कोलकाता का गेंदबाजी आक्रमण कमजोर हुआ है। हर्षित राणा और आकाश दीप बाहर हो चुके हैं। मथीशा पथिराना को अभी श्रीलंका क्रिकेट से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मिलना बाकी है। इसके अलावा 25.20 करोड़ रुपये में खरीदे गए ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन फिलहाल सिर्फ बल्लेबाज के रूप में उपलब्ध हैं। उसके गेंदबाजी आक्रमण की कमजोरी मुंबई के खिलाफ पहले मैच में साफतौर पर नजर आई जहां उसकी टीम 220 रन का बचाव नहीं कर सकी थी। रोहित और रयान रिकेल्टन ने केवल 72 गेंद पर 148 रन की साझेदारी कर दी थी। उसके मुख्य स्पिनरों सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती को संघर्ष करना पड़ा था। यह उनकी टीम के लिए चिंता का विषय होगा।

कुल मैच	: 30
कोलकाता जीता	: 20
हैदराबाद जीता	: 10

रहाणे से आस

कोलकाता मैच के लिए टर्निंग विकेट तैयार करने के बारे में सोच रहा है लेकिन तब भी 200 का स्कोर औसत माना जाएगा। कोलकाता का कप्तान अजिंक्य रहाणे की अच्छी शुरुआत से हौसला बढ़ा होगा।

नंबर गेम

02 मुकाबले पिछली बार दोनों ने खेले थे जिसमें से एक हैदराबाद और एक कोलकाता ने जीता था

03 साल से ईडन गार्डस में जीती नहीं है हैदराबाद की टीम कोलकाता से। पिछली जीत 2023 में दर्ज की थी

54 मैच जीते हैं कोलकाता ने 2008 से ईडन गार्डस में खेले गए 94 मुकाबलों में से

भारतीय टीम का जुलाई में होगा जिम्बाब्वे दौरा

- तीन टी-20 मैचों की सीरीज खेलेगी

एजेंसी। नई दिल्ली

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम जुलाई 2026 में जिम्बाब्वे दौरे पर तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला खेलेगी। इस श्रृंखला के सभी मुकाबले हरारे स्थित हरारे स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित किए जाएंगे। श्रृंखला की शुरुआत 23 जुलाई से होगी और चार दिनों के भीतर तीनों मैच संपन्न होंगे। भारतीय टीम का जिम्बाब्वे दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के बीच टीम प्रबंधन को नए और युवा खिलाड़ियों को मौका देने का अवसर मिल सकता है। इससे टीम संयोजन में बदलाव और नए चेहरों को परखने की संभावना भी रहेगी। भारत ने आखिरी बार वर्ष 2024 में जिम्बाब्वे का दौरा किया था, जहां दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टी-20 श्रृंखला खेली गई थी।

श्रृंखला का कार्यक्रम

जुलाई 2026 में आयोजित होने वाली इस रोमांचक टी-20 श्रृंखला के तहत सभी तीनों मुकाबले हरारे में खेले जाएंगे, जिसकी शुरुआत 23 जुलाई (गुरुवार) को पहले मैच से होगी, जिसके बाद 25 जुलाई (शनिवार) को दूसरा और 26 जुलाई (रविवार) को तीसरा मैच खेला जाएगा। इस विदेशी दौरे के समापन के बाद, जिम्बाब्वे की टीम जनवरी 2027 में भारत का जवाबी दौरा करेगी, जहाँ दोनों देशों के बीच तीन मैचों की एकदिवसीय (ODI) अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला खेली जाएगी; इन मैचों की मेजबानी भारत के प्रमुख शहरों कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई द्वारा की जाएगी।

न्यूज़ ब्रीफ

बीमारी के बाद राडुकानू एक और टूर्नामेंट से हटीं

लंदन। ग्रेट ब्रिटेन की युवा टेनिस खिलाड़ी एमा राडुकानू ने डब्ल्यूटीए 500 इवेंट से नाम वापस ले लिया है। उनके प्रतिनिधियों के अनुसार, वायरल बीमारी से ठीक होने के बाद उन्होंने अपने क्ले-कोर्ट सीजन की शुरुआत में देरी की है। माना जा रहा है कि 23 साल की राडुकानू क्ले कोर्ट पर लौटने से पहले पूरी तरह ठीक होने पर ध्यान देना चाहती हैं। दुनिया की 28वें नंबर की खिलाड़ी ने पिछले महीने इंडियन वेल्स में हिस्सा लिया था, लेकिन फिर मियामी छोड़ने का फैसला किया। राडुकानू को 22 अप्रैल से होने वाले मैड्रिड ओपन में वापसी की उम्मीद है, जो यूरोपियन क्ले-कोर्ट सीजन का पहला डब्ल्यूटीए 1000 इवेंट है। उन्होंने इस सीजन में छह टूर्नामेंट खेले हैं, जिनमें 14 मैचों में से सात जीते हैं।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ग्लेन मैक्सवेल को अनुबंध सूची से किया बाहर

सिडनी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अनुभवी ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को 2026-27 सीजन के लिए केंद्रीय अनुबंध सूची से बाहर कर दिया गया है। इस फैसले से 37 वर्षीय मैक्सवेल के अंतरराष्ट्रीय करियर पर सवाल उठ रहे हैं। CA ने टेस्ट में नियमित रूप से खेलने वाले 21 खिलाड़ियों की सूची जारी की है, जिसमें मैक्सवेल का नाम शामिल नहीं है। मैक्सवेल ने आखिरी टेस्ट मैच 2017 में खेला था और तब से वह टेस्ट क्रिकेट की योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं।

इराक की जीत के साथ ही विश्व कप की 48 टीमें तय

एजेंसी। मॉन्टेरी

विश्व कप फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट के लिए ढाई साल से चली क्वालीफाइंग प्रक्रिया के बाद सभी 48 टीमें तय हो गई हैं। यहां मंगलवार को अंतरमहाद्वीपीय प्लेऑफ में इराक ने बोलीविया को 2-1 से हराकर 48वां और अंतिम स्थान हासिल किया। यह मैच बोस्निया हर्जेगोविना की यूरोपीय प्लेऑफ में चार बार के चैंपियन इटली पर पेनाल्टी शूटआउट में उलटफेर भरी जीत के बाद खेला गया।विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाली एक अन्य टीम कांगो थी जिसने मैक्सिको के ग्वाडालाजारा में जमैका को 1-0 से हराया। स्वीडन, तुर्किए

और चेक गणराज्य तीनों ने यूरोपीय प्लेऑफ से क्वालीफाई किया है। स्वीडन ने पोलैंड को, तुर्किए ने कोसोवो को और चेक गणराज्य ने डेनमार्क को हराया।विश्व कप 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। यह पहला अवसर होगा जबकि टूर्नामेंट में 48 टीमें भाग लेंगी। फाइनल 19 जुलाई को होगा।

विश्व कप के ग्रुप

- ग्रुप ए : चेक गणराज्य, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया
- ग्रुप बी : कनाडा, बोस्निया हर्जेगोविना, कतर, स्विट्जरलैंड
- ग्रुप सी : ब्राजील, हैती, मोरक्को, स्कॉटलैंड
- ग्रुप डी : ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, तुर्किए, अमेरिका
- ग्रुप ई : कुराकाओ, इक्वाडोर, जर्मनी, आइवरी कोस्ट
- ग्रुप एफ : नीदरलैंड, जापान, स्वीडन, ट्यूनीशिया
- ग्रुप जी : बेल्जियम, मिस्र, ईरान, न्यूजीलैंड
- ग्रुप एच : केप वर्डे, सऊदी अरब, स्पेन, उरुग्वे
- ग्रुप आई : फ्रांस, नॉर्वे, सेनेगल, इराक

न्यूजीलैंड की महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराया

एजेंसी। वेलिंगटन

कप्तान अमेलिया केर (नाबाद 179) के शतक से न्यूजीलैंड की महिला टीम ने बुधवार को दूसरे एकदिवसीय मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को दो गेंद रहते दो विकेट से हरा दिया। इसके साथ मेजबान ने तीन मैच की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। टॉस हारकर दक्षिण अफ्रीका ने 50 आवरों में छह विकेट पर 346 रन बनाए। अन्नेका बोश ने 91 रन की पारी खेली। ब्री इलिंग को तीन और केली नाइट को दो विकेट मिले। जवाब में

न्यूजीलैंड ने 49.2 ओवरों में आठ विकेट पर 350 रन बनाकर मैच दो विकेट से जीत लिया। न्यूजीलैंड के लिए केर के अलावा इसाबेला गेज ने 68 रन की पारी खेली। इनके अलावा अन्य बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सकीं।

सुरक्षा प्रोटोकॉल उल्लंघन पर पीसीबी के नए दिशा-निर्देश

एजेंसी। लाहौर

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहां एक टीम होटल में सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने के बाद पाकिस्तान सुपर लीग की सभी टीमों को ताजा दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उसने स्पष्ट किया है कि आइंदा किसी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।रजा ने शुक्रिया किया : लाहौर कलंदर्स के लिए खेल रहे जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि वह अपने परिजनों से टीम होटल में मिलने की अनुमति देने के लिए पीसीबी के शुक्रगुजार हैं। इसके बाद पीसीबी ने सभी आठ टीमों और अन्य अधिकारियों को ईमेल भेजा। पीसीबी ने ईमेल में कहा कि कोई भी खिलाड़ी या अधिकारी कम से कम 24 घंटे पहले बोर्ड से अनुमति लिए बिना टीम होटल में किसी परिजन से नहीं मिल सकता।जगह तय होगी : सूत्र ने बताया कि बोर्ड ने इसके साथ ही स्पष्ट किया कि खिलाड़ियों के लिए उनके परिजनों से मुलाकात के लिए

टीम होटल में कोई जगह तय की जाएगी। सूत्र ने कहा, बोर्ड ने साफतौर पर कहा कि खिलाड़ी की पत्नी, माता पिता, भाई या बहन ही उनके कमरे के भीतर जा सकते हैं और वह भी बोर्ड से 24 घंटे पहले अनुमति लेने के बाद।

बॉलीवुड

'राजा शिवाजी' का टीजर रिलीज

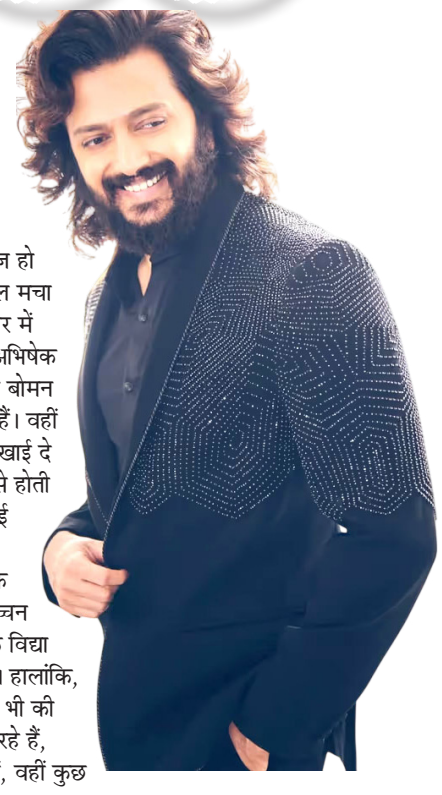

अभिनेता रितेश देशमुख की बहुप्रतीक्षित ऐतिहासिक फिल्म 'राजा शिवाजी' का टीजर आखिरकार रिलीज हो गया है, जिसने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। टीजर में रितेश, छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार में बेहद प्रभावशाली और दमदार नजर आ रहे हैं। फिल्म में अभिषेक बच्चन, जेनेलिया डिसूजा, विद्या बालन, फरदीन खान और बोमन ईरानी जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। वहीं संजय दत्त मुगल सेनापति अफजल खान के किरदार में दिखाई दे रहे हैं। टीजर की शुरुआत संजय दत्त की दमदार आवाज से होती है, जिसमें वह कहते हैं, ₹नाम के आगे राजा लगाने से कोई राजा नहीं बनता है।₹ इसके बाद मराठाओं और मुगलों के बीच भीषण युद्ध के दृश्य देखने को मिलते हैं, जो फिल्म के भव्य स्तर और एक्शन को दर्शाते हैं। टीजर में अभिषेक बच्चन संभाजी शाहजी भोसले के किरदार में नजर आते हैं, जबकि विद्या बालन भी अपने किरदार से खास प्रभाव छोड़ती दिखती हैं। हालांकि, टीजर देखने के बाद कुछ दर्शकों ने इसकी तुलना छावा से भी की है। सोशल मीडिया पर यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जहां कुछ लोग रितेश के इस अवतार की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ का मानना है कि विक्की कौशल की 'छावा' को टक्कर देना आसान नहीं होगा। फिर भी, मराठी पृष्ठभूमि से आने वाले रितेश देशमुख को इस ऐतिहासिक किरदार में देखने के लिए दर्शक उत्साहित हैं। खास बात यह है कि 'राजा शिवाजी' का निर्देशन भी खुद रितेश देशमुख ने किया है। यह फिल्म 1 मई 2026 को हिंदी, मराठी और तेलुगु भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। भव्य स्केल और दमदार स्टारकास्ट के चलते फिल्म को लेकर दर्शकों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं।

'क्वीन 2' के साथ वापसी को तैयार कंगना रनौत

अभिनेत्री कंगना रनौत की चर्चित फिल्म 'क्वीन' अब अपने सीक्वल के साथ लौटने जा रही है। साल 2014 में रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन विकास बहल ने किया था, जिसमें कंगना के अभिनय को खूब सराहा गया और उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। फिल्म में राजकुमार राव मुख्य भूमिका में नजर आए थे, जबकि लीजा हेडन ने खास कैमियो किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, 'क्वीन 2' की शूटिंग अप्रैल के आखिर तक शुरू होने वाली है। फिल्म में रानी का किरदार पहले से ज्यादा सशक्त और आत्मनिर्भर नजर आएगा, जिसकी कहानी एक नए मोड़ के साथ आत्म-खोज की यात्रा को दर्शाएगी। जहां पहली फिल्म में रानी पेरिस और एम्स्टर्डम गई थी, वहीं इस बार कहानी भारत के अलग-अलग शहरों में आगे बढ़ेगी। सूत्रों के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग मुंबई के एक स्टूडियो में भव्य सेट के साथ शुरू होगी, जिसमें उत्तर भारतीय शहर का माहौल तैयार किया जाएगा। मुंबई शेड्यूल पूरा होने के बाद टीम अन्य महानगरों में भी शूटिंग करेगी। फिल्म को करीब तीन महीने में पूरा करने की योजना है। वर्कफ्रंट की बात करें तो कंगना इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को लेकर भी चर्चा में हैं, जो मुंबई में हुए 26/11 मुंबई आतंकी हमला के दौरान कामा अस्पताल के कर्मचारियों की कहानी पर आधारित होगी।

हिंदी सीखना रहा सबसे बड़ी चुनौती: कुब्रा सैत

कुब्रा सैत इन दिनों संकल्प में अपने दमदार पुलिस अधिकारी 'परवीन' के किरदार को लेकर चर्चा में हैं। प्राइम वीडियो पर हाल ही में रिलीज हुई इस वेब सीरीज में कुब्रा ने अपने रोल को पूरी मेहनत और समर्पण के साथ निभाया है। उन्होंने बताया कि इस किरदार की तैयारी केवल शूटिंग के दौरान ही नहीं, बल्कि उससे पहले और बाद में भी जारी रही। खास तौर पर शुद्ध हिंदी बोलना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती रही, जिसके लिए उन्होंने विशेष मेहनत की। सीरीज में पहली बार नाना पाटेकर के साथ काम करने को लेकर कुब्रा ने इसे बेहद प्रेरणादायक अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर जैसे दिग्गज कलाकार सेट पर अपने व्यवहार और अनुशासन से बहुत कुछ सिखा जाते हैं। "वे खुद अपने स्क्रिप्ट्स लिखते हैं और शूटिंग के दौरान पूरी तरह काम में डूबे रहते हैं। ये छोटी-छोटी बातें ही असल सीख देती हैं," उन्होंने कहा। कुब्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि हर कलाकार का काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन उन्होंने नाना पाटेकर से बहुत कुछ सीखा। अपने करियर और सीनियर कलाकारों के साथ काम करने के अनुभव पर कुब्रा ने कहा कि उन्हें कभी डर नहीं लगा। उनके अनुसार, डर अक्सर हमारे मन की बनाई कहानी होता है। "अगर हम पहले से सोच लें कि सामने वाला सीनियर है और डांटेगा, तो वही हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है," उन्होंने कहा। कुब्रा सैत इससे पहले भी कई बार पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा चुकी हैं, लेकिन उन्होंने टाइपकास्ट होने की धारणा को खारिज किया। उनका कहना है कि हर किरदार अलग होता है और कोई भी दो भूमिकाएं एक जैसी नहीं हो सकतीं। वहीं, अपने करियर के उतार-चढ़ाव पर उन्होंने सकारात्मक नजरिया रखते हुए कहा कि उन्हें अपने सफर में केवल आगे बढ़ने के मौके ही नजर आए हैं। "कभी बड़ी तो कभी छोटी छलांग मिलती है, लेकिन मैं लगातार आगे बढ़ रही हूं।

रणबीर कपूर ने फिल्म 'रामायण' पर की बात

बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर इन दिनों अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' को लेकर सुर्खियों में हैं, जो दिवाली 2026 पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हाल ही में लॉस एंजिल्स में फिल्म की एक विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई, जहां दर्शकों को रणबीर के 'श्रीराम' अवतार की झलक दिखाई गई। इस पर अभिनेता ने मीडिया से बातचीत में एक दिलचस्प खुलासा किया, जिसने फैंस को हैरान कर दिया।

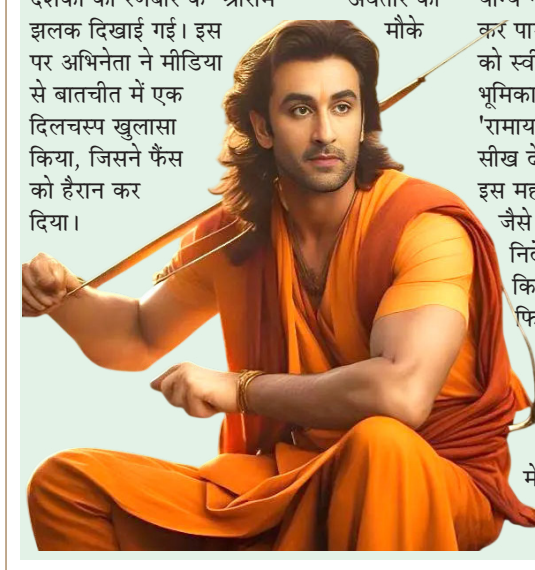

रणबीर ने बताया कि जब निर्माता नमित मल्होत्रा ने उन्हें पहली बार 'श्रीराम' की भूमिका का प्रस्ताव दिया था, तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। अभिनेता ने कहा, ₹करीब चार साल पहले जब मुझे यह रोल ऑफर हुआ, तो मेरी पहली प्रतिक्रिया नहीं थी। मुझे लगा कि मैं इसके लिए योग्य नहीं हूं और इस किरदार के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा।₹ हालांकि बाद में उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और पूरे समर्पण के साथ इस भूमिका के लिए तैयार हुए। उन्होंने आगे कहा कि 'रामायण' केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि एक सीख देने वाली कहानी है। रणबीर के मुताबिक, इस महाकाव्य से सहानुभूति, प्रेम और समानता जैसे मूल्यों को समझने का मौका मिलता है। निर्देशक नितेश तिवारी के विजन ने उन्हें इस किरदार को अपनाने के लिए प्रेरित किया। फिल्म में साई पल्लवी 'सीता', यश 'रावण', सनी देओल 'हनुमान' और रवि दुबे 'लक्ष्मण' के किरदार में नजर आएंगे। भव्य पैमाने पर बन रही यह फिल्म भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक मानी जा रही है, जिसे लेकर दर्शकों में भारी उत्साह है।

बॉक्स ऑफिस पर फिर छाएंगी नयनतारा

नयनतारा एक बार फिर बड़े पर्दे पर छाने की तैयारी में हैं। जवान से बॉलीवुड में सफल शुरुआत के बाद अब वे कई बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं। खास तौर पर सलमान खान के साथ उनकी फिल्म SVC63 को लेकर काफी चर्चा है, जिसकी शूटिंग अप्रैल 2026 से शुरू हो सकती है। उनकी अन्य अपकमिंग फिल्मों में टॉक्सिक शामिल है, जिसमें वे यश के साथ नजर आएंगी और यह 4 जून 2026 को रिलीज होगी। वहीं पैट्रियट एक मल्टीस्टारर स्पाई-थ्रिलर है, जिसमें मोहनलाल और ममूटी जैसे दिग्गज शामिल हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, मूकूथी अम्मन 2, हाय मूवी, मन्नांगट्टी सिंस 1960 और रक्कायि जैसी फिल्में भी उनकी झोली में हैं। लगातार अलग-अलग जॉनर की फिल्मों के साथ नयनतारा अपने करियर के सबसे व्यस्त दौर में हैं और एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाने के संकेत दे रही हैं।

वॉर ब्रीफ

जंग की वजह से ईरान में 1.15 लाख से ज्यादा इमारतें क्षतिग्रस्त

तेहरान। जंग की वजह से देशभर में 1.15 लाख से ज्यादा इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इनमें घर, अस्पताल, स्कूल और राहत केंद्र शामिल हैं। साथ ही 1,500 से ज्यादा लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया है।

होर्मुज के रास्ते 94,000 टन एलपीजी लेकर 2 जहाज भारत पहुंचे

नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। यूएई से एलपीजी (रसोई गैस) लेकर आए दो टैंकर होर्मुज स्ट्रेट पार करके सुरक्षित रूप से भारत पहुंच गए हैं। पहला टैंकर BW TYR 31 मार्च को मुंबई पहुंचा। यह जहाज यूएई के रास अल खैमाह से चला था और करीब 6 दिन में भारत पहुंचा। इसमें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के लिए गैस लाई गई है। दूसरा टैंकर BW ELM 1 अप्रैल को न्यू मैंगलोर के पास पहुंचा। यह जहाज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए LPG लेकर आया है। इन दोनों जहाजों में कुल मिलाकर लगभग 94,000 टन LPG भारत पहुंची है। दोनों जहाजों पर 50 से ज्यादा भारतीय नाविक भी मौजूद थे। सरकार के मुताबिक, अब तक 8 भारतीय जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं।

जंग से मिडिल ईस्ट को 18 लाख करोड़ का नुकसान

तेहरान। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) की हालिया रिपोर्ट मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के विनाशकारी आर्थिक परिणामों की ओर इशारा करती है, जिसके अनुसार इस संघर्ष के कारण पूरे क्षेत्र की GDP में 3.7% से 6% तक की भारी गिरावट आ सकती है। इस युद्ध से लगभग 18 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है, जो न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को भी प्रभावित कर रहा है, विशेषकर होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही में 70% से अधिक की कमी दर्ज की गई है। तेल की कीमतें आसमान छूते हुए 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच गई हैं, जिससे ऊर्जा संकट गहरा गया है, और सबसे गंभीर मानवीय पहलू यह है कि इस अस्थिरता के कारण 16 लाख से 36 लाख नौकरियों पर सीधे तौर पर संकट मंडरा रहा है।

ईरान में इस्लामिक गार्ड के हाथ में पूरा कंट्रोल

ईरान में तख्तापलट!

एजेंसी । तेहरान

ईरान के भीतर निर्वाचित सरकार और सुरक्षा बल (IRGC) के मध्य मतभेद गहराने की सूचना है। 'तेहरान टाइम्स' की एक रिपोर्ट के अनुसार, ताकतवर सैन्य संस्था इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और राष्ट्रपति मसूद पजशकियान के बीच सत्ता संघर्ष चरम पर पहुँच गया है। दावा है कि IRGC ने अब देश की पूरी बागडोर अपने नियंत्रण में ले ली है। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि राष्ट्रपति पजशकियान को सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनेई से भेंट करने से भी रोका जा रहा है। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन और तेहरान के मध्य जारी तनाव को कम करने हेतु बातचीत चल रही है। ट्रंप के मुताबिक, उनकी टीम ईरान के कुछ 'तार्किक' नेतृत्वकर्ताओं के साथ संपर्क में है ताकि युद्ध के हालात टाले जा सकें। हालांकि, ईरान ने ट्रंप के इन दावों का तत्काल खंडन करते हुए कहा कि कोई भी प्रत्यक्ष संवाद नहीं हो रहा है। इस विरोधाभास के बाद यह बहस छिड़ गई कि वास्तव में ईरान की सत्ता का केंद्र कहाँ है।

- आईआरजीसी-सरकार के बीच टकराव
- राष्ट्रपति को सुप्रीम लीडर मुजतबा से मिलने से रोका

सरकार के फैसलों पर भारी पड़ रही आईआरजीसी

खबरों के अनुसार, राष्ट्रपति पजशकियान अपनी स्वतंत्र इच्छा से निर्णय लेने में असमर्थ हैं। जिस IRGC का मुख्य उत्तरदायित्व अमेरिकी खतरों से निपटना था, वह अब नागरिक प्रशासन के मुख्य कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। सूत्रों ने बताया कि पजशकियान ने 26 मार्च को हुसैन देहगान को नया खुफिया मंत्री नियुक्त करना चाहा था, किंतु IRGC प्रमुख अहमद वहीदी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वहीदी ने यह कमान तब संभाली जब युद्ध के आरंभ में पूर्व कमांडर मोहम्मद पाकपुर की मृत्यु हो गई थी। वहीदी का तर्क है कि युद्धकाल में सभी संवेदनशील नियुक्तियाँ सेना की परिषद द्वारा ही तय की जाएंगी। ईरानी प्रोटोकॉल के तहत, खुफिया मंत्री की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सुप्रीम लीडर की सहमति अनिवार्य होती है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा पर अंतिम निर्णय उन्हीं का होता है।

व्यापारिक मार्गों और संसाधनों पर भी कब्जा

ईरान में शीर्ष स्तर पर पैदा हुए इस शून्य का लाभ उठाकर IRGC अब एक समानांतर सरकार की तरह सक्रिय है। 1979 की क्रांति के बाद अस्तित्व में आई यह सेना अब मात्र रक्षक नहीं, बल्कि तेल, बैंकिंग और निर्माण जैसे बड़े उद्योगों की मालिक है। विश्व के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य पर भी अब सेना का पूर्ण अधिकार है, जिसे वर्तमान में अवरुद्ध रखा गया है। मुजतबा खामेनेई की स्थिति को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। चर्चा है कि या तो वे कोमा में हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है। ट्रंप और अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने भी उनकी शारीरिक स्थिति को लेकर गंभीर संकेत दिए हैं।

सत्ता के ढांचे पर सेना की मजबूत पकड़

रिपोर्ट बताती है कि ईरान में सर्वोच्च नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। 28 फरवरी को संघर्ष शुरू होने के साथ ही अयातुल्लाह अली खामेनेई और कई वरिष्ठ हस्तियों के मारे जाने की खबर थी। उनके उपरांत मुजतबा खामेनेई को नेतृत्व सौंपा गया, परंतु वे सार्वजनिक रूप से कहीं दिखाई नहीं दिए। उनके नाम से संदेश केवल टीवी पर प्रसारित हो रहे हैं। अब IRGC के आला अफसरों की एक 'मिलिट्री काउंसिल' दैनिक प्रशासन चला रही है। सुरक्षा के नाम पर मुजतबा को एकांतवास में रखा गया है और उन तक सरकारी फाइलें भी नहीं पहुँचने दी जा रही हैं। राष्ट्रपति पजशकियान और मुजतबा के बीच संवाद पूरी तरह कट चुका है। राष्ट्रपति ने कई बार मिलने का प्रयास किया, जिसे सैन्य अधिकारियों ने दरकिनार कर दिया। पजशकियान इस बात से चिंतित हैं कि सेना की आक्रामक नीतियों और पड़ोसियों पर हमलों से देश की अर्थव्यवस्था ढह रही है। हफ्तों लंबे युद्ध ने संसाधनों और हथियारों के भंडार को काफी कम कर दिया है।

ईरान से बहुत जल्द निकलेंगे, फिर लौटेंगे: ट्रंप

एजेंसी । वाशिंगटन

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। बुधवार को रॉयटर्स से बातचीत में उन्होंने कहा कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान से बाहर निकल जाएगा और जरूरत पड़ने पर कुछ जगहों पर कार्रवाई के लिए वापस लौट सकता है। यह बयान उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करने से कुछ घंटे पहले दिया।

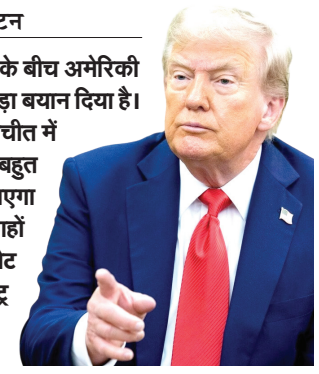

इस दौरान ट्रंप ने नाटो पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि गठबंधन ईरान में अमेरिकी उद्देश्यों के लिए समर्थन नहीं दे रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह नाटो से अमेरिका को वापस बुलाने के विकल्प पर 'पूरी तरह से' विचार कर रहे हैं। वहीं, जब उनसे पूछा गया कि ईरान युद्ध कब समाप्त माना जाएगा? इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि मैं आपको ठीक-ठीक तारीख नहीं बता सकता... हम बहुत जल्द इससे बाहर निकल जाएंगे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी कार्रवाई ने सुनिश्चित कर दिया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। ट्रंप ने आगे कहा कि उनके पास परमाणु हथियार नहीं होंगे क्योंकि वे अभी इसके काबिल नहीं हैं। फिर मैं चला जाऊंगा और सबको अपने साथ ले जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम वापस आकर छिटपुट हमले कर सकते हैं।

युद्धविराम चाहता है ईरान

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनके द्वारा अमेरिकी जनता को संबोधित करने से पहले ईरान के राष्ट्रपति युद्धविराम चाहते हैं। ट्रंप ने यह दावा अपनी 'ट्रुथ सोशल' पर किया। ट्रंप ने 'ईरान के नये शासन के राष्ट्रपति' शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि ईरान में राष्ट्रपति बदले नहीं हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि युद्धविराम तभी होगा जब होर्मुज जलडमरूमध्य 'खुला, सुरक्षित और बाधारहित' होगा। उन्होंने आगे लिखा कि तब तक हम ईरान को पूरी तरह तबाह कर रहे हैं, या जैसा लोग कहते हैं, उसे वापस पाषाण युग में भेज रहे हैं। हालांकि ट्रंप के इस पोस्ट पर ईरान की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने मंगलवार देर रात अल जजीरा के साथ एक साक्षात्कार में लड़ाई जारी रखने की तेहरान की तत्परता का संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि आप ईरान की जनता से धमकियों और समयसीमा की भाषा में बात नहीं कर सकते। हम आत्मरक्षा के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं करते हैं।

ट्रम्प का भाषण बेअसर: ईरान

ईरान के एक सीनियर अफसर ने कहा कि ट्रम्प के भाषण को लेकर कहा कि उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। अधिकारी ने कहा कि ट्रम्प बहुत अस्थिर और अजीब इंसान हैं। उनके बयान को बहुत महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। ट्रम्प गुरुवार सुबह 6:30 बजे (भारतीय समय के मुताबिक) संबोधित करेंगे। इसमें वे ईरान जंग को लेकर बातचीत कर सकते हैं। अभी यह साफ नहीं है कि वे क्या ऐलान करेंगे।

ब्रिटेन ने भी छोड़ा ट्रंप का साथ

यह हमारी जंग नहीं है : ब्रिटिश प्रधानमंत्री

लंदन। पूरा पश्चिम एशिया युद्ध की आग में सुलग रहा है। इस्राइल और अमेरिका ने मिलकर सबसे पहले ईरान पर हमला किया। बदले में ईरान ने आस-पास के सभी दुश्मन देशों को निशाना बनाया। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों से मदद की अपील की। लेकिन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ईरान युद्ध में शामिल न होने के अपने रुख पर अडिग हैं। दरअसल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री स्टार्मर ने कहा कि ब्रिटेन, ईरान के खिलाफ अमेरिका और इस्राइल के सैन्य अभियान में शामिल नहीं होगा। उन्होंने साफ-साफ कहा कि यह हमारी लड़ाई नहीं है।

ईरान जंग में शामिल हो सकता है यूएई

- होर्मुज को जबरन खोलने में अमेरिका की करेगा मदद

एजेंसी । अबू धाबी

संयुक्त अरब अमीरात US-ईरान जंग में सीधे तौर पर शामिल होने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, यूएई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाने की

कोशिश कर रहा हैं। इस प्रस्ताव में होर्मुज स्ट्रेट को जबरन खोलने के लिए सभी तरीकों का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी जा रही है। इसके तहत हार्मुज सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाएगी, जो जहाजों की सुरक्षा

यूएई दूसरे देशों से गठबंधन बनाने की मांग कर रहा

यूएई अमेरिका, यूरोप और एशिया से अपील कर रहा है कि वे गठबंधन बनाकर स्ट्रेट को सुरक्षित करें। यूएई अधिकारी ने WSJ को बताया कि ईरान अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा है, इसलिए वह वैश्विक अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने को तैयार है। यूएई का मानना है कि अगर UNSC से प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाए तो वर्तमान में झिझक रहे एशियाई और यूरोपीय देश भी हार्मुज को खुलवाने में मदद करने के लिए आगे आ सकते हैं।

सबसे बड़ी मुकदमेबाज है सरकार : सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी । नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार देश की सबसे बड़ी मुकदमेबाज है, जिसकी वजह से अदालतों पर मामलों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील को खारिज करते हुए की।

एससीबीए कॉन्फ्रेंस के बयान का उल्लेख

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के एक हालिया सम्मेलन का भी जिक्र किया, जिसमें जस्टिस नागरत्ना ने कहा था कि मुकदमों की बढ़ती संख्या के लिए सरकार की भूमिका अहम है। कोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की बात दोहराई।

हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने पर नाराजगी

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि आखिर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की जरूरत क्या थी। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में अनावश्यक अपीलें न्यायिक व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव डालती हैं।

अपील खारिज, 25 हजार का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए केंद्र सरकार की अपील को खारिज कर दिया। साथ ही अदालत ने सरकार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिससे यह संकेत दिया गया कि गैर-जरूरी मुकदमों को बढ़ावा देना स्वीकार्य नहीं है।

सरकार को कानूनी विवेक अपनाने की सलाह

पीठ ने कहा कि यदि हाईकोर्ट किसी सजा को असंगत मानते हुए राहत देता है, तो ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने से बचना चाहिए। अदालत ने सुझाव दिया कि सरकार को इस तरह के मामलों में पहले उचित कानूनी राय लेनी चाहिए। जस्टिस नागरत्ना ने जोर देकर कहा कि अदालतों में लंबित मामलों के भारी बोझ के लिए सरकार काफी हद तक जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी मुकदमेबाजी की नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए।

सरकारी मुकदमों के आंकड़े चिंताजनक

कानून मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 तक सरकार से जुड़े लगभग 7.14 लाख मामले लंबित थे। इनमें वित्त मंत्रालय के 1.94 लाख, भारतीय रेलवे के 1.11 लाख और रक्षा मंत्रालय के 94 हजार से अधिक मामले शामिल हैं, जो न्यायिक प्रणाली पर बढ़ते दबाव को दर्शाते हैं।

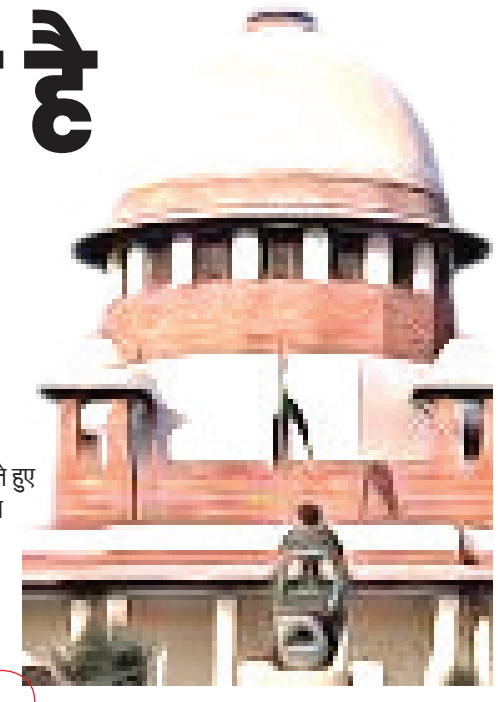

सीआईएसएफ अधिकारी का मामला क्या था

यह मामला केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के एक अधिकारी की बर्खास्तगी से जुड़ा था। अधिकारी पर 11 दिनों तक अनुपस्थित रहने और अनुशासनहीनता के आरोप लगाए गए थे। हालांकि, हाईकोर्ट ने पाया कि वह मेडिकल छुट्टी पर था और दूसरे आरोप में भी कोई ठोस आधार नहीं था।

अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने का बिल लोकसभा से पारित

भाजपा-कांग्रेस ने दिया समर्थन

एजेंसी । नई दिल्ली

अमरावती को आंध्र प्रदेश की स्थायी और एकमात्र राजधानी के रूप में मान्यता देने वाला बिल बुधवार को लोकसभा से पारित हो गया। भाजपा और तेदेपा के साथ ही कांग्रेस ने भी इस बिल का समर्थन किया। हालांकि आंध्र प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी वाईएसआरसीपी ने इस बिल का विरोध किया। लोकसभा में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 पर बहस शुरू करते हुए कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से बिल का समर्थन करती है, लेकिन राज्य को विशेष दर्जा भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'अमरावती को बंगलूरू, चेन्नई या हैदराबाद की तरह विकसित किया जाए। विशाखापत्तनम, तिरुपति और कुर्नूल को भी विकसित किया जाए। हम अमरावती को आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी मानते हैं।'

पहली बार किसी जगह को राजधानी बनाने का विधेयक संसद में पेश

आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी तेदेपा के सांसद और केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं संचार राज्यमंत्री चंद्र शेखर पेम्मासानी ने भी सदन से अपील की कि बिल को सर्वसम्मति से पास किया जाए ताकि आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी मिल सके। भाजपा सांसद सीएम रमेश ने कहा कि यह आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है जब संसद में किसी स्थान को राज्य की राजधानी घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि अमरावती को स्थायी राजधानी बनाने से कोई इसे बदल नहीं सकेगा। उन्होंने पूर्व की वाईएसआरसीपी की सरकार द्वारा तीन राजधानियों की योजना को तर्कहीन और अव्यवहारिक बताया। वहीं, वाईएसआर कांग्रेस के सांसद पीवी मिधुन रेड्डी ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि किसानों के हितों की सुरक्षा और मुआवजे की स्पष्ट समयसीमा के बिना इस बिल का कोई मतलब नहीं है।

लूथरा ब्रदर्स को मिली जमानत, लेकिन रहेंगे जेल में

एजेंसी । पणजी

. गोवा के चर्चित 'बिर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब अग्निकांड मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। मर्सेस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने क्लब के मालिकों, गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को नियमित जमानत दे दी है। अदालत में वरिष्ठ वकील सुबोध कांतक और वकील वैभव सूरी ने आरोपियों का पक्ष रखा। अदालत से जमानत मिलने के बावजूद दोनों भाई अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। मापुसा पुलिस ने सोमवार को इन दोनों भाइयों को अपनी हिरासत में ले लिया है। यह कार्रवाई फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) बनाने के आरोप में की गई है। पुलिस का आरोप है कि इन लोगों ने आबकारी विभाग से लाइसेंस लेने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर वाला दस्तावेज इस्तेमाल किया था।

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला 6 दिसंबर 2025 को अरपोरा स्थित नाइटक्लब में लगी भीषण आग से जुड़ा है। उस दर्दनाक हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आग लगने के बाद दोनों आरोपी थाईलैंड भाग गए थे, जिन्हें 17 दिसंबर को वहां से वापस भारत लाया गया था। तब से वे उत्तरी गोवा की कोलवाले जेल में बंद हैं। मामले में अंजुना पुलिस जब इस अग्निकांड की जांच कर रही थी, तभी फर्जी दस्तावेजों का मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार, क्लब चलाने के लिए जरूरी कागजात गलत तरीके से तैयार किए गए थे।

त्रिशूर चुनाव पर विवाद

केंद्रीय मंत्री गोपी की याचिका खारिज

- केरल हाईकोर्ट ने कहा-मुकदमे का सामना करना होगा

एजेंसी । गुवाहाटी

केरल हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका के खिलाफ दायर उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने यह फैसला सुनाया। अब सुरेश गोपी को इस मामले में कोर्ट में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। त्रिशूर के रहने वाले और एआईवाईएफ नेता बिनॉय एएस ने सुरेश गोपी के

खिलाफ यह चुनावी याचिका दायर की थी। बिनॉय ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि सुरेश गोपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान गलत तरीके अपनाए। याचिका के अनुसार, उन्होंने चुनाव जीतने के लिए धार्मिक प्रतीकों का गलत इस्तेमाल किया। सुरेश गोपी वर्तमान में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं।

सीएपीएफ बिल को लेकर संग्राम

- राज्यसभा में 'केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026' ध्वनि मत से पारित

एजेंसी । नई दिल्ली

बुधवार को संसद में सियासी घमासान देखने को मिला। दरअसल, राज्यसभा में 'केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026' को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। विपक्ष ने बिल को आनन-फानन में पास करने का आरोप लगाया है। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट भी कर दिया।

सदन में जमकर हुई बहस

सदन में बहस का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साफ कहा कि यह बिल देश के संघीय ढांचे को कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत करता है। इससे भर्ती प्रक्रिया बेहतर होगी और जवानों का मनोबल बढ़ेगा। दूसरी ओर, विपक्ष ने मांग की कि इस बिल को संसद की प्रवर समिति के पास भेजा जाए। जब सरकार ने यह मांग नहीं मानी, तो नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अगुवाई में समूचा विपक्ष नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चला गया।

बिल में ऐसा क्या है?

अभी तक देश के अलग-अलग अर्धसैनिक बलों के लिए सेवा और प्रशासन के नियम भी अलग-अलग थे। यह बिल उन सभी को हटाकर एक सिंगल सिस्टम लागू करेगा। लेकिन असली पेंच फंसा है आईपीएस अफसरों की तैनाती को लेकर। इस नए कानून के तहत, सीएपीएफ में आईजी रैंक के 50 फीसदी पद और एडीजी रैंक के कम से कम 67 फीसदी पद आईपीएस अधिकारियों के लिए रिजर्व रहेंगे। विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। पिछले ही साल अक्तूबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक रिव्यू पिटीशन खारिज करते हुए कहा था कि अर्धसैनिक बलों में आईपीएस अफसरों की संख्या धीरे-धीरे कम की जाए, जिससे वहां बरसों से काम कर रहे कैडर अधिकारियों को प्रमोशन मिल सके।